वर्ष 12 • अंक 293 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 28 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 3

बकाया शुल्क अग्रिम चुकाएंगी दूरसंचार फर्में

केकी मिस्त्री ▶▶ पृष्ठ 2

एचडीएफसी का कर पूर्व लाभ दोगुना से ज्यादा बढ़ा

डॉलर रु. 71.40 ▲ 10 पैसे | यूरो रु. 78.80 ▲ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40651 ▲ 655 रुपये | सेंसेक्स 41155.10 ▼ 458.10 | निफ्टी 12119.30 ▼ 129.30 | निफ्टी फ्यूचर्स 12166.30 ▲ 47.30 | ब्रेंट क्रूड 58.60 डॉलर ▼ 01.40 डॉलर

एक नज़र

इंडिगो को 496 करोड़ रुपये का मुनाफा

निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी इंडिगो का परिचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन का दिसंबर 2019 तिमाही में शुद्ध लाभ तेजी से बढ़कर 496 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी की अधिक आय इसकी वजह रही। पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसका कर पूर्व लाभ 186 करोड़ रुपये रहा था। दिसंबर 2019 तिमाही में कंपनी की आय 10,330.2 करोड़ रुपये रही जो 2018-19 की दिसंबर तिमाही में 8,229.3 करोड़ रुपये थी। पृष्ठ 2

कोरोना वायरस से वैश्विक बाजारों में दहशत

चीन में कोरोना विषाणु के संक्रमण का वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ने की आशंका से दुनिया के कई बाजारों में बिकवाली का जोर रहा। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 458.07 अंक की गिरावट के साथ 41,155.12 पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 129.25 अंक गिरकर 12,119 पर बंद हुआ। चीन में कोरोना विषाणु प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ने की खबर के बाद इसके वैश्विक आर्थिक प्रभाव को लेकर आशंका बढ़ी है। इसके कारण दुनिया भर के बाजारों में उतार-चढ़ाव देखा गया।

वुहान में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी

चीन में कोरोना वायरस के असर को देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। कैबिनेट सचिव ने चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण से पैदा हालात की सोमवार को समीक्षा की। बैठक में फैसला किया गया कि वुहान से भारतीयों को बाहर निकालने की तैयारी के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए विदेश मंत्रालय चीन के अधिकारियों से अनुरोध करेगा। उधर, जहाजरानी मंत्रालय उन अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों पर लोगों की जांच आरंभ करेगा जहां चीन से लोग आते हैं, वहीं अमृतसर हवाईअड्डे पर यात्रियों की जांच के लिए थर्मल जांच उपकरण लगाए गए हैं। सरकार नेपाल की सीमा पर सतर्कता बढ़ाने की तैयारी की है। इस बीच चीन से वापस आई एक महिला को पटना में वायरस के लक्षणों को देखते हुए भर्ती कराया गया है। चीन की यात्रा से हैदराबाद आए तीन लोगों को निगरानी में रखा गया है।

आईटीआई एफपीओ को 9 फीसदी आवेदन

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आईटीआई लिमिटेड के एफपीओ निर्गम को सोमवार को 9 फीसदी आवेदन प्राप्त हुए। कंपनी का एफपीओ मंगलवार को बंद होगा। निर्गम का मूल्य दायरा 72 से 77 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। बाजार में आईटीआई के शेयर का बंद भाव 89 रुपये है।

आज का सवाल

क्या नई शर्तों से एयर इंडिया के लिए आकर्षित होंगे खरीदार

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या कर संग्रह में कमी से बढ़ेगी सरकार की मुश्किल?	हां	88.46%
	नहीं	11.54%

एयर इंडिया के लिए नियमों में ढील

संभावित बोलीदाताओं को लुभाने के लिए बिक्री की शर्तों को बनाया आकर्षक

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 27 जनवरी

प्रबंधन पर पूर्ण नियंत्रण, कर्ज में कमी और कंसोर्टियम बनाने की सहूलियत के जरिये सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के सौदे को आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। सरकार ने एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के साथ ही उसकी सहायक इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ ही एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज के विनिवेश के लिए आज प्रारंभिक बोली आमंत्रित की है। मूल्य के लिहाज से सरकार की ओर से यह सबसे बड़ी निजीकरण की कवायद होगी।

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'पिछले साल एयर इंडिया के लिए कोई बोली नहीं मिली थी। उसके बाद हमने महत्त्वपूर्ण परिदृश्य का विश्लेषण किया और इस बार उसे ज्यादा आकर्षक बनाने का प्रयास किया है।'

सरकार ने कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिसमें पिछले साल की तुलना में इस बार एयर इंडिया का कर्ज और देनदारी का करीब 30 फीसदी खुद वहन करने की घोषणा की है। सरकार एयर इंडिया का 23,286.50 करोड़ रुपये का कर्ज नए मालिक को हस्तांतरित करेगी और मौजूदा देनदारियों का बड़ा हिस्सा खुद वहन करने का निर्णय किया है। करीब 22,000 करोड़ रुपये की देनदारियों में से नए मालिक को संपत्तियों के एवज में लिया जाएगा।

बिक्री प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने कहा कि एयर इंडिया की स्थिर परिसंपत्तियां इस बार बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है जो 2018 में 27,000 करोड़ रुपये थी। बिक्री दस्तावेज में कहा गया है कि एयर इंडिया के कुल बेड़े का करीब 56 फीसदी विमानन कंपनी के स्वामित्व में है और नए मालिक कर्ज को कम करने के लिए इन विमानों की बिक्री करने और पट्टा वापस करने में सक्षम होंगे। नए शर्तों के अनुसार कर्ज और ब्याज लागत में करीब 61 फीसदी कम की गई है जो मार्च 2018 में 35 फीसदी कम किया गया था।

दीपम के सचिव तुहीन कांत पांडेय ने कहा कि एयर इंडिया की परिसंपत्तियां विमानन कंपनी की देनदारी के बराबर हैं और नए मालिक को कोई अतिरिक्त देनदारी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, 'सभी विलय और अधिग्रहण इस सिद्धांत पर होते हैं कि खरीदार को बराबर देनदारी और परिसंपत्ति दी जाएगी। इस मामले में भी हमने सुनिश्चित किया है कि सरकार अतिरिक्त देनदारी अपने हाथ में लेगी।'

पिछली बार के उलट सरकार ने इस बार कर्मचारियों के लिए शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि कितने समय तक नए मालिक को इन कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखना होगा। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि खरीदारों को कर्मचारियों से कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि उनकी संख्या कंपनी के परिचालन के आकार के अनुपात में है। एयर इंडिया के पास हर विमान पर 133 कर्मचारी हैं जबकि सिंगापुर एयरलाइंस के पास प्रति विमान 136 कर्मचारी हैं। एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अश्वनी लोहानी ने कहा, 'जो भी इतनी बड़ी विमानन कंपनी का परिचालन करेगा, उसे कर्मचारियों की जरूरत होगी।' (शेष पृष्ठ 2 पर)

एयर इंडिया के लिए बिक्री आवेदन

- एयर इंडिया में 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
- कर्ज के बड़े हिस्से की खुद वहन करेगी सरकार
- एयर इंडिया के प्रबंधन पर नए मालिक का होगा पूर्ण नियंत्रण
- बोलीदाता की नेटवर्थ होनी चाहिए 3,500 करोड़ रुपये, पहले 5,000 करोड़ रुपये की थी शर्त
- लॉक-इन अवधि होगी एक साल, पहले तीन साल रखी गई थी यह अवधि

बजट से निवेश में तेजी की उम्मीद

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जनवरी

- निवेशकों को दी जा सकती है कर रियायतें
- परिचालन नियमों में भी ढील की संभावना
- राजस्व लक्ष्य होंगे ज्यादा मुमकिन
- गैर-कर राजस्व बढ़ाने पर होगा जोर

देश में निवेश के माहौल में सुधार के लिए आम बजट में निजी निवेशकों को कई तरह की रियायतें दी जा सकती हैं। अधिकारियों के मुताबिक साथ ही अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने के लिए परिचालन नियमों में भी कुछ ढील दिए जाने की संभावना है।

सूत्रों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में कर लक्ष्यों को हासिल करना अब मुश्किल लग रहा है। इसके मद्देनजर अगले वित्त वर्ष के लिए ज्यादा मुमकिन लक्ष्य घोषित किए जाएंगे। साथ ही आम बजट में बजट से इतर खर्च का भी जिक्र किया जाएगा जिससे राजकोषीय घाटे की असली तस्वीर सामने आएगी।

सूत्रों का कहना है कि राजस्व मोर्चे पर गैर-कर राजस्व को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश को शामिल किया जा सकता है।

उन सार्वजनिक कंपनियों की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण पर जोर दिया जाएगा जिनमें सरकार की शत प्रतिशत हिस्सेदारी है।

खपत बढ़ाने के लिए आय कर में कटौती की संभावना के बारे में सूत्रों का कहना है कि सरकार की राजकोषीय स्थिति को देखते हुए व्यापक कर सुधार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसे देने के लिए कर ढांचे में कुछ बदलाव हो सकता है।

अधिकारियों के मुताबिक बजट को इस दृष्टिकोण से तैयार किया जाएगा कि अर्थव्यवस्था का बुरा दौर बीत चुका है और अब वह पटरी पर लौट रही है। निवेश बढ़ाने के लिए लाभांश वितरण कर (टीटीडी) को खत्म किया जा सकता है। यह उन शेयरधारकों पर लगाया जा सकता है जो लाभांश पाते हैं। साथ ही दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर में भी बदलाव किया जा सकता है। (शेष पृष्ठ 14 पर)

कारोबारियों का डेटाबेस तैयार करेगी केंद्र सरकार!

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जनवरी

- कारोबारी व उसके कारोबार के साथ ही कर्मचारी की होगी जानकारी
- इस डेटाबेस की कारोबारियों के लिए नीति बनाने में मदद लेगी सरकार

केंद्र सरकार की कारोबारियों का डेटाबेस तैयार करने की योजना है। इससे कारोबारियों के लिए योजनाएं बनाते समय यह पता करने में मदद मिलेगी कि संबंधित योजना से कितने कारोबारियों को लाभ होगा। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के कारोबारी सम्मेलन में कारोबारियों से कारोबारी डेटाबेस तैयार करने में मदद करने को कहा । गोयल ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोग अपने बारे में जानकारी देने से डर रहे हैं। ऐसे में कारोबारी संगठनों को कारोबारी डेटाबेस तैयार करने में मदद करनी चाहिए क्योंकि इस डेटा के आधार पर कारोबारियों की सहायता के लिए नीति बनाने में मदद मिलेगी। कारोबारी संगठन अपने अपने सदस्य कारोबारियों और कर्मचारियों की जानकारी एकत्र कर सरकार को दें। इस जानकारी में कारोबारी का नाम, संपर्क, ई-मेल, पता और कौन सा कारोबार कर रहे हैं, दुकान या फैक्टरी में कितने कर्मचारी काम करते हैं और इन कर्मचारियों की सामान्य जानकारी शामिल होनी चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन कॉमन फॉर्म शुरू किया जा सकता है। इस डेटाबेस को प्रस्तावित राष्ट्रीय खुदरा नीति से भी जोड़ा जा सकता है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि कैट अपने 40 हजार कारोबारी संगठनों के माध्यम से 6 महीने के अंदर सरकार को कारोबारी डेटाबेस मुहैया कराने में मदद करेगा। गोयल ने इस कार्यक्रम में कारोबारियों द्वारा उठाए गए वित्त पोषण संबंधी समस्या, मुद्रा में कठिनाई, चेक बाउंस के मामलों के जल्द निपटारे, कारोबारियों को रेलवे से ढुलाई कराने में आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव बाद बैठक करने का भरोसा दिया।

सामान्य बीमा फर्मों में पूंजी निवेश जल्द

नम्रता आचार्य
कोलकाता, 27 जनवरी

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के चालू वित्त वर्ष में विलय की दिशा में बड़ी प्रगति करने की उम्मीद है। आम बजट 2020-21 के दो हफ्ते पहले सार्वजनिक क्षेत्र की तीन सामान्य बीमा कंपनियों - नैशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक मंडल ने विलय के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी है। ऐसे में बहुप्रतीक्षित विलय की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। मामले के जानकार सूत्रों का कहना है कि कंपनियां जल्द ही 12,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की भी उम्मीद कर रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र की एक सामान्य बीमा फर्म के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कई महीने पहले वित्तीय सेवाओं के विभाग ने करीब 12,000 करोड़ रुपये का पूंजी डालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ऐसे में उम्मीद है कि यह पैसा जल्द ही मिल सकता है। विलय प्रक्रिया में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में अब इस दिशा में तेजी आने की संभावना है।'

एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'बोर्ड की मंजूरी इस बात का संकेत है कि सरकार विलय को लेकर गंभीर है। हालांकि पूंजी निवेश के बिना विलय कारगर नहीं होगी। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि विलय से पहले सरकार सामान्य बीमा कंपनियों में पूंजी डाल सकती है।' इस बीच, तीनों सामान्य बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं है और उन्हें पूंजी की तत्काल जरूरत है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के अंत में नैशनल बीमा सॉल्वेंसी अनुपात 1.04 था जबकि नियामकीय आवश्यकता 1.5 है। यूनाइटेड इंडिया का सॉल्वेंसी अनुपात चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1.05 रही, जो नियामकीय जरूरत से कम है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार कंपनी को 20 सितंबर, 2019 में 1,091 करोड़ रुपये का कर पूर्व घाटा हुआ था। इसी तरह चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ओरिएंटल इंश्योरेंस का सॉल्वेंसी अनुपात 1.56 रहा। सितंबर तिमाही के अंत में कंपनी को 330 करोड़ रुपये का कर पूर्व घाटा हुआ था। तीनों कंपनियां सामान्य बीमा लोक उपक्रम संघ के तहत आती हैं और उसने विलय योजना का खाका तैयार करने के लिए ईवाई को सलाहकार नियुक्त किया था। ईवाई ने दिसंबर 2020 तक या जुलाई से लेकर 19 महीने के अंदर विलय प्रक्रिया पूरी करने की सिफारिश की।

सामान्य बीमा कंपनियों का लेखाजोखा

कंपनी	सॉल्वेंसी अनुपात	घाटा	एकीकृत कर अनुपात (फीसदी में)
नैशनल इंश्योरेंस	1.04 (2019 की चौथी तिमाही तक)	--	--
ओरिएंटल इंश्योरेंस	1.56 (2020 की दूसरी तिमाही तक)	330	137
यूनाइटेड इंडिया	1.05 (2020 की दूसरी तिमाही तक)	1,091	139.8

नोट : घाटा और एकीकृत कर अनुपात सितंबर 2019 तक। घाटा करोड़ रुपये में।
स्रोत : जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऐंड पब्लिक डिस्क्लोजर।

खबरों में रहे स्टॉक

टाटा स्टील

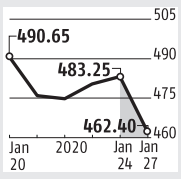

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे ज्यादा टूटने वाला शेयर

₹ 483.25 पिछला बंद भाव
₹ 462.40 आज का बंद भाव
▼ 4.31 %

एपीएल अपोलो ट्यूब्स

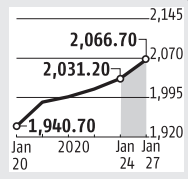

तीसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 111 करोड़ रुपये रहा

₹ 2,031.20 पिछला बंद भाव
₹ 2,066.70 आज का बंद भाव
▲ 1.75 %

वॉकहार्ट

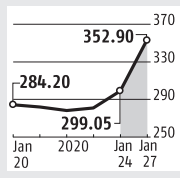

पिछले साल हुए घाटे के मुकाबले कर पूर्व लाभ16 करोड़ रुपये रहा

₹ 299.05 पिछला बंद भाव
₹ 352.90 आज का बंद भाव
▲ 18.01 %

बैंक ऑफ बड़ौदा

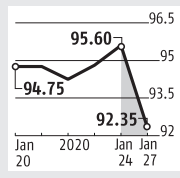

तीसरी तिमाही में शुद्ध एनपीए बढ़कर 4.05 फीसदी रहा

₹ 95.60 पिछला बंद भाव
₹ 92.35 आज का बंद भाव
▼ 3.40 %

टीसीआई एक्सप्रेस

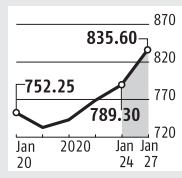

तीसरी तिमाही में एबिटा मार्जिन 107 आधार अंक बढ़कर 13.1 फीसदी रहा

₹ 789.30 पिछला बंद भाव
₹ 835.60 आज का बंद भाव
▲ 5.87 %

संक्षेप में

टॉरंट फार्मा के लाभ में 2 फीसदी की मामूली बढ़त

दवा कंपनी टॉरंट फार्मास्युटिकल्स का एकीकृत शुद्ध लाभ 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 2.03 फीसदी बढ़कर 251 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में उसे 246 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी की एकीकृत आय 2019-20 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 1,966 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2,051 करोड़ रुपये थी। *भाषा*

भूषण स्टील: पूर्व अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भूषण स्टील के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी नितिन जौहरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्हें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने कथित तौर पर धोखाधड़ी गतिविधियों में लिप्त रहने पर गिरफ्तार किया था। जौहरी को पिछले साल अगस्त में उच्च न्यायाल द्वारा दी गई जमानत को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ब्रजेश सेठी ने यह फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने इससे पहले फैसला सुनाते हुए मामले में नए सिरे से सुनवाई करने को कहा था। शीर्ष अदालत का आदेश एसएफआईओ की अपील पर आया, जिसमें उच्च न्यायालय के 14 अगस्त 2019 के फैसले को चुनौती दी गई थी। *भाषा*

इंडिगो ने दर्ज किया 496 करोड़ रुपये कर पश्चात लाभ

एजेंसियां
नई दिल्ली/मुंबई/हैदराबाद, 27 जनवरी

किफायती विमानन सेवा कंपनी इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का कर पश्चात लाभ दिसंबर तिमाही में बढ़कर 496 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जिसे मुख्य रूप से उच्च आय का सहारा मिला। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी का कर पश्चात लाभ 185.2 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी की कुल आय इस अवधि में 25.5 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 10,330.2 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 8,229.3 करोड़ रुपये रही थी। इसमें यात्री टिकट से राजस्व सालाना आधार पर 24.1 फीसदी बढ़कर 8,770.30 करोड़ रुपये रहा जबकि सहायक राजस्व 1,037.30 करोड़ रुपये, यानी इसमें सालाना आधार पर 28.8 फीसदी की उछाल दर्ज हुई।

औसत टिकट कीमत में दिसंबर तिमाही में 2.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 3.88 रुपये प्रति किलोमीटर हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 3.83 रुपये प्रति किलोमीटर रही थी। कंपनी की ईंधन लागत 2 फीसदी घटकर 334.19 करोड़ रुपये रह गई।

इंडिगो के मुख्य कार्याधिकारी रोनोजॉय दत्ता ने कहा, जिस तरह से हम अपने नोटवर्क को विकसित कर रहे हैं, बड़े व छोटे शहरों को जोड़ रहे हैं, उसे हम काफी उत्साहित हैं ताकि ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा विकल्प उपलब्ध हो। हमने शिरडी व शिलॉन्ग जैसे शहरों को अपने नेटवर्क से जोड़ा है , वहीं हनोई व ग्वांगझू जैसे अहम शहरों तक भी पहुंच रहे हैं। विमानन कंपनी ने सात नए अंतरराष्ट्रीय मार्ग और 17 नए देसी मार्ग पर परिचालन शुरू किया है और तिमाही के दौरान रोजाना अधिकतम 1,634 उड़ानों का परिचालन किया। विस्तार के दौरान कंपनी ग्राहक सेवा पर भी काफी ध्यान दे रही है। कंपनी ने कहा कि सालाना आधार पर प्रति सीट किलोमीटर की उपलब्धता में इजाफा मार्च तिमाही में 20 फीसदी रहने की संभावना है और 2019-20 में 23 फीसदी। कंपनी का कुल नकद शेष 20,068 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 9,412 करोड़ रुपये की मुक्त नकदी और 10,656 करोड़ रुपये प्रतिबंधित नकदी शामिल है। तिमाही में इंडिगो ने 12 विमान जोड़े। कंपनी के बेड़े में 257 विमान थे।

डॉ. रेड्डीज को नुकसान

विश्लेषकों के अनुमान के उलट दवा कंपनी डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज ने दिसंबर तिमाही में 569.7 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान दर्ज किया। इस अवधि में राजस्व में ठीक-ठाक बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी को 1,320 करोड़ रुपये का नुकसान एम्पेयरमेंट चार्जेज के तौर पर हुआ। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी का कर पूर्व लाभ 580.5 करोड़ रुपये रहा था जबकि शुद्ध लाभ 485.2 करोड़ रुपये। कंपनी के मुताबिक, जेनेरिक की पेशकश और दिसंबर 2019 में नुवेरिंग के अधिकृत तौर पर उतारे जाने से डीआरएल के जेनेरिक नुवेरिंग उत्पाद की वैल्यू में ठीक-ठाक कमी आई। इसी लिहाज से कंपनी ने 1,110 करोड़ रुपये का एम्पेयरमेंट चार्ज का हिसाब रखा। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बाजार के मौजूदा आयाम को ध्यान में रखते हुए अन्य उत्पादों के मामले में भी 210 करोड़ रुपये के एम्पेयरमेंट चार्ज का हिसाब रखा।

इस अवधि में कंपनी का राजस्व 14 फीसदी उछलकर 4,383.8 करोड़ रुपये रहा। इसकी वजह उभरते बाजारों, भारत, यूरोपीय बाजार में वैश्विक जेनेरिक कारोबार रही, जिसने क्रमश: 19 फीसदी, 13 फीसदी और 52 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की।

अमेरिकी बाजार में वैश्विक जेनेरिक बिक्री 8 फीसदी बढ़कर 1,599.9 करोड़ रुपये रही, जो कुल राजस्व में 36 फीसदी का योगदान करता है। फार्मास्युटिकल सर्विसेज ऐंड ऐक्टिव इनग्रेडिएंट्स से राजस्व 16 फीसदी बढ़कर 690.6 करोड़ रुपये रहा।

एचडीएफसी का कर पूर्व लाभ 219 फीसदी बढ़ा

सुब्रत पांडा
मुंबई, 27 जनवरी

हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैंस कॉरपोरेशन (एचडीएफसी) का कर पूर्व लाभ दिसंबर तिमाही में 9,143 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 2,868.80 करोड़ रुपये के मुकाबले 219 फीसदी ज्यादा है।

हालांकि लाभांश, निवेश की बिक्री, उचित मूल्यांकन में बदलाव और नुकसान के लिए प्रावधान से पहले लाभ सालाना आधार पर 7 फीसदी बढ़कर 3,075.43 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 2,873.62 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी को तीसरी तिमाही में गृह फाइनैंस से निवेश निकालने पर 9,020 करोड़ रुपये का फायदा हुआ, जिसका विलय बंधन बैंक के साथ हुआ। गृह फाइनैंस एचडीएफसी की अफोर्डेबल हाउसिंग लोन इकाई थी। एचडीएफसी का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 8,372.49 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 2,113.80 करोड़ रुपये के मुकाबले 296 फीसदी ज्यादा है।

तिमाही में कंपनी का प्रावधान काफी तेजी से बढ़ा। कंपनी ने 2,995 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो पिछले साल की समान अवधि में 116 करोड़ रुपये था। एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केकी मिस्त्री ने कहा, प्रावधान के मामले में हम काफी संकीर्ण रहे हैं। इन वर्षों में हमने इसी नीति का अनुपालन किया और हम ऐसे ही बने हुए हैं। दिसंबर 2019 में समाप्त नौ महीने में कुल प्रावधान 4,639 करोड़ रुपये रहा। बैलेंस शीट के स्तर पर वास्तविक प्रावधान 9,934 करोड़ रुपये रहा।

मिस्त्री ने कहा, अगर हमें डिफॉल्ट के समय के आधार पर प्रावधान करना होता तो हमें कुल 3,624 करोड़ रुपये का प्रावधान करना होता। इसके बजाय हमने 6,310 करोड़ रुपये ज्यादा यानी 9,934 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। डिफॉल्ट में फंसे निवेश के लिहाज से प्रावधान 2.25 फीसदी है।

दिसंबर तिमाही में एचडीएफसी का सकल एनपीए 1.36 फीसदी रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 1.22 फीसदी रहा था। वैयक्तिक क्षेत्र में एनपीए मामूली बढ़कर 0.75 फीसदी र हा, जो पहले 0.68 फीसदी रहा था। इसी तरह गैर-वैयक्तिक श्रेणी में एनपीए 2.91 फीसदी रहा, जो पहले 2.46 फीसदी रहा था।

एचडीएफसी की शुद्ध ब्याज आय सालाना आधार पर 9 फीसदी बढ़कर 3,240 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 2,984 करोड़ रुपये र ही थी। शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.3 फीसदी रहा, जो पहले 3.4 फीसदी रहा था। एचडीएफसी की लोनबुक इस अवधि में 13.4 फीसदी बढ़कर 4.41 लाख करोड़ रुपये रही। आज एचडीएफसी का शेयर बीएसई पर 2.25 फीसदी की गिरावट के साथ 2,395.80 रुपये पर बंद हुआ।

ब्राजील की टॉरस आर्म्स संग जिंदल डिफेंस का करार :ओ पी जिंदल के स्वामित्व वाली जिंदल डिफेंस ने ब्राजील की टॉरस आर्म्स एसए के साथ संयुक्त उपक्रम (जेवी) समझौता कर भारत में छोटे हथियार निर्माण में अपने प्रवेश की घोषणा की है। शुरुआती 50 लाख डॉलर के निवेश वाली इस परियोजना को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा। इस समझौते में हरियाणा के हिसार में एक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव शामिल है। *बीएस*

बजट से पहले पीएसयू शेयरों पर दांव सुरक्षित

पुनीत वाधवा और दीपक कोरगांवकर
नई दिल्ली, 27 जनवरी

वित्त वर्ष 2020 में कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के शेयरों पर दबाव बना हुआ है। निफ्टी सीपीएसई सूचकांक में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। तुलनात्मक तौर पर, निफ्टी-50 सूचकांक में इस अवधि में 55 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है। विश्लेषकों का कहना है कि कुछ खास पीएसयू में सरकार द्वारा हिस्सेदारी बिक्री में संभावित विलंब की वजह से सूचकांक पर दबाव दिखा है।

निफ्टी सीपीएसई सूचकांक का गठन कुछ खास सीपीएसई में कुछ हिस्सेदारी की बिक्री के लिए सरकार की पहल को आसान बनाने के लिए किया गया था। वित्त वर्ष 2020 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एसजेवीएन (5 और 9 प्रतिशत की तेजी) को छोड़कर सूचकांक में शामिल शेष सात शेयरों ने कमजोर प्रतिफल दिया है।

जहां एनबीएफसी में 45 प्रतिशत की कमजोरी आई, वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसीएल), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया में 25 से 27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। एनएलसी इंडिया और कोल इंडिया में भी करीब 20 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई।

22 जनवरी को सूचकांक में लगभग 4 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 1,788 अंक के साथ 52 सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुआ था। शेयरों में ऑयल इंडिया और आईओसीएल ने अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर बनाए।

जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों ने एक ताजा रिपोर्ट में कहा, 'ओएनजीसी को लेकर भी सरकारी हिस्सेदारी बिक्री पर गतिरोध बना हुआ है और हमें अल्पावधि में इसका समाधान निकलने की संभावना नहीं है। हालांकि कच्चे तेल के मजबूत परिदृश्य के साथ हम भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में कुछ अपस्ट्रीम निवेश का सुझाव देना चाहेंगे। गैस कारोबार में ओएनजीसी की बिक्री वृद्धि मजबूत होगी, जबकि तेल कीमतों के सीमित दायरे में रहने से उसे उचित लाभांश भुगतान में मदद मिल सकती है।'

कम कर राजस्व संग्रह की वजह से सरकार के पास भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी दूर करने के लिए सीमित खर्च की संभावना रह गई है। कई अनुमानों के अनुसार, जहां सरकार वित्त वर्ष 2020 के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपये के अपने महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य से चूक सकती है, वहीं आगामी बजट में राजस्व कमी को दूर करने के लिए अगले वित्त वर्ष में विनिवेश प्राप्ति पर फिर से निर्भरता बनी रह सकती है।

ब्रिकवर्क रेटिंग्स में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. एम गोविंदा राव ने कहा, 'रिपोर्टों के अनुसार, सरकार को 2019-20 के दौरान अब तक विनिवेश प्रक्रिया से 18,094.59 करोड़ रुपये की पूंजी मिली है, जबकि बजटीय अनुमान 1.05 लाख करोड़ रुपये का है। कई रणनीतिक बिक्री में विलंब के साथ, सरकार आगामी बजट में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के विनिवेश से अन्य 1 लाख करोड़ रुपये हासिल होने की घोषणा कर सकती है।'

पीएसयू पर दबाव

बीएसई भाव (रुपये में)

नाम	29 मार्च, 2019	27 जनवरी 2020	बदलाव %
एनबीसीसी	66.3	37.05	-44.12
आईओसीएल	162.85	117.45	-27.88
ओएनजीसी	159.75	117.25	-26.60
ऑयल इंडिया	185.45	141.30	-23.81
कोल इंडिया	237.2	193.25	-18.53
एनटीपीसी	134.7	113.15	-16.00
एनएलसी इंडिया	69.4	59.00	-14.99
पावर फाइनैंस कॉर्प.	123.1	115.85	-5.89

बीएस रिसर्च ब्यूरो द्वारा संकलित

गिफ्ट सिटी में पीएफसी ने सूचीबद्ध कराया बॉन्ड

श्रेया जय
नई दिल्ली, 27 जनवरी

पावर फाइनैंस कंपनी (पीएफसी) ने पहली बार अपने 75 करोड़ डॉलर के अंतरराष्ट्रीय बॉन्डों को एनएसई-आईएफएससी गिफ्ट सिटी में सूचीबद्ध कराया है। इस बॉन्ड को इंडिया आईएनएक्स और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध कराया जाएगा। पीएफसी की तरफ से यह एक चरण में उतारा गया पहला सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड है। 10.25 साल में परिपक्व होने वाला 75 करोड़ डॉलर का बॉन्ड पिछले हफ्ते उतारा गया। इस बॉन्ड पर 3.95 फीसदी ब्याज देय है और इसे कुल मिलाकर 2.2 अरब डॉलर की बोली मिली। वित्त वर्ष 2020 में यह पीएफसी का तीसरा अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड है।

इस वित्त वर्ष में दबाव वाली 4 और बिजली परिसंपत्तियों के समाधान पर नजर

बिजली क्षेत्र की सबसे बड़ी एनबीएफसी पीएफसी ने इस बॉन्ड के जरिये अपने पोर्टफोलियो में विदेशी उधारी की हिस्सेदारी बढ़ाई है। बॉन्ड जारी करने के बाद पीएफसी पहली भारतीय सार्वजनिक कंपनी बन गई जिसने 10 साल से ज्यादा अवधि वाला वरिष्ठ असुरक्षित डॉलर बॉन्ड जारी किया है।

पीएफसी के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक राजीव शर्मा ने कहा, पिछले तीन साल से पीएफसी अपनी उधारी के पोर्टफोलियो को विशाखित करने की कोशिश कर रही है और विदेशी बाजार से अब तक 5 अरब डॉलर जुटाए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में हमारी नजर 12 अरब डॉलर की उधारी पर है, जो कुल उधारी का 25 फीसदी है। अभी पीएफसी की बकाया विदेशी मुद्रा उधारी 6.5 अरब डॉलर से ज्यादा है।

बिजली वितरण क्षेत्र के लिए नई योजना

सरकारी स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए सुधार पर केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा, हमें उम्मीद है कि इश साल के आम बजट में डिस्कॉम के सुधार के लिए नई योजना आएगी। सिंह ने कहा, हमने नई योजना के बारे में जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय से हमने चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि नई योजना को बजट में जगह मिलेगी।

श्रीराम कैपिटल का मुनाफा पांच साल में हुआ दोगुना

टी ई नरसिम्हन और गिरीश बाबू
चेन्नई, 27 जनवरी

श्रीराम समूह की वित्तीय सेवाओं और बीमा व्यवसाय की प्रमुख निवेश कंपनी श्रीराम कैपिटल (एससीएल) पांच साल में अपना कर-बाद समेकित लाभ दोगुना करने में सफल रही है।

कंपनी की कुल आय वित्त वर्ष 2019 में बढ़कर 5,407 करोड़ रुपये हो गई जो पांच साल में लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि है। कंपनी का कर-बाद लाभ (पीएटी) जहां वित्त वर्ष 2015 में 842.7 करोड़ रुपये था वहीं वित्त वर्ष 2019 में यह बढ़कर 1,737 करोड़ रुपये (हालांकि वित्त वर्ष 2016 में यह घटकर 759.8 करोड़ रुपये पर आ गया था) हो गया।

वित्त वर्ष 2019 में यह आंकड़ा पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के 1,330 करोड़ रुपये की तुलना में 30.6 प्रतिशत बढ़ा। अगस्त 2018 में आईएलऐंडएफएस द्वारा ऋणों पर चूक दर्ज किए जाने के बाद एनबीएफसी क्षेत्र में पैदा हुए संकट के बावजूद यह मजबूती देखने को मिली।सहायक कंपनियों के तौर पर समूह के स्वामित्व वाली कंपनियों में श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस (74.56 प्रतिशत हिस्सेदारी) और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस (76.66 प्रतिशत) शामिल हैं। इसकी सूचीबद्ध कंपनियों में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस कंपनी (एसटीएफसी) और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनैंस (एससीयूएफ) शामिल है और इनकी शेयरधारिता 26.08 प्रतिशत तथा 33.74 प्रतिशत है।

परिचालन कर रहीं मुख्य सहायक कंपनियों में से एक श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (एसएलआईसी) का कारोबार 2018-19 में बढ़कर 1,644 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2015 में 1,080 करोड़ रुपये था। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, वित्त वर्ष 2019 में कुछ नए व्यवसायों में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सेगमेंट के निजी क्षेत्र में यह 16 प्रतिशत थी और सरकारी कंपनी एलआईसी के लिए इसमें एक प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। कर-बाद लाभ 74.1 करोड़ रुपये रहा जबकि वित्त वर्ष 2015 में यह 79.7 करोड़ रुपये था। वहीं वित्त वर्ष 2016 में यह घटकर 18.4 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2017 में 15.7 करोड़ रुपये था।

एयर इंडिया के लिए नियमों में ढील

पृष्ठ 1 का शेष

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के प्रबंधन का नियंत्रण छोड़ने और कर्ज अपने हाथ में लेने के फैसले से निवेशकों को सकारात्मक संदेश गया है। दक्षिण एशिया में एविएशन कंसल्टिंग फर्म सीएपीए के मुख्य कार्याधिकारी कपिल कौल ने कहा, 'सरकार ने साहसिक फैसला लिया है। सरकार ने आकर्षक पेशकश की है और हम उम्मीद करते हैं कि निवेशक इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे।' अलबत्ता, संभावित बोलीदाताओं ने इस बारे में सीधे तौर पर कोई प्रतिबद्धता दिखाने से परहेज किया। एक भारतीय विमानन कंपनी के अधिकारी ने कहा कि निवेशकों के लिए यह सौदा आसान नहीं होगा।

उन्होंने कहा, 'परिचालन राजस्व से 23 हजार करोड़ रुपये के ऋण के ब्याज का भुगतान करना आसान नहीं है। नए मालिक को कंपनी के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार करना होगा। मुझे लगता है कि यह मुश्किल काम है।' अलबत्ता, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिया कि इस बार सरकार ने बोलीकर्ताओं तक अपनी बात को बेहतर तरीके से पहुंचाया है और वह कुछ शर्तों में बदलाव को तैयार है।

उन्होंने कहा, पिछली बार सरकार बेहद सतर्क थी क्योंकि हम चुनाव में जा रहे थे। इस बार हम गृह मंत्री अमित शाह की अगुआई में साहसिक कदम उठाने को तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि एयर इंडिया को नया खरीदार मिल जाएगा।'

बकाया शुल्क अग्रिम चुकाएंगी दूरसंचार फर्में

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 27 जनवरी

- **अगर सभी फर्में अग्रिम भुगतान करती हैं तो सरकार को लगभग 34,773 करोड़ रुपये की पूंजी हासिल होगी**
- **इसमें लाइसेंस शुल्क के तौर पर 23,182 करोड़ रुपये और एसयूसी के लिए 11,591 करोड़ रुपये का बकाया शामिल है**
- **हालांकि आशंका जताई जा रही है कि भुगतान न करने की वजह से सरकार इन दूरसंचार फर्मों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है**

प्रमुख दूरसंचार कंपनियां बकाया लाइसेंस शुल्क और एजीआर पर आधारित स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता शुल्कों (एसयूसी) को अग्रिम तौर पर चुकाने के प्रस्ताव पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ चर्चा कर रही हैं, बशर्ते कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दूरसंचार कंपनियों की संशोधन याचिका में उनके पक्ष में निर्णय आए जिसकी सुनवाई इस सप्ताह होगी। मूल रकम में दूरसंचार कंपनियों द्वारा चुकाए जाने वाले लाइसेंस शुल्क और उनके एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) की उनकी व्याख्या पर आधारित एसयूसी के बीच अंतर शामिल है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने पर ब्याज शामिल नहीं है।

यदि इस पहल पर अमल होता है तो इससे तीन ऑपरेटरों भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा समूह से सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 में 22,077 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हासिल होगा। यह दूरसंचार राजस्व से 2019-20 में 50,519 करोड़ रुपये के बजटीय लक्ष्य से ज्यादा है। नई याचिका के जरिये इन तीन दूरसंचार कंपनियों ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि उन्हें बकाया के भुगतान की शर्तों और समय को लेकर डीओटी के साथ चर्चा करने की अनुमति दी जाए।

हालांकि यदि सभी दूरसंचार कंपनियां अग्रिम भुगतान करती हैं तो सरकार को लगभग 34,773 करोड़ रुपये (रिलायंस जियो को छोड़कर, जो 195 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर चुकी है) की बड़ी पूंजी हासिल होगी। इसमें लाइसेंस शुल्क के तौर पर 23,182 करोड़ रुपये और एसयूसी के लिए 11,591 करोड़ रुपये का बकाया शामिल है।

दूरसंचार कंपनियों द्वारा चुकाई जाने वाली यह अग्रिम राशि उनके कुल बकाया का लगभग 25 प्रतिशत है।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक राजन मैथ्यू ने इस संबंध में वार्ताओं की जानकारी देते हुए कहा, 'हम दूरसंचार विभाग के साथ चर्चा कर रहे हैं और मूल एजीआर को अग्रिम तौर पर चुकाए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि इस संबंध में निर्णायक रूपरेखा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगी। हमारा अनुमान है कि प्रमुख ऑपरेटरों को लगभग 25,000 करोड़ रुपये की रकम चुकानी होगी।'

सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल के अंत में दूरसंचार कंपनियों को एजीआर बकाया के तौर पर 147,000 करोड़ रुपये का भुगतान 90 दिन के अंदर करने का निर्देश दिया था। दूरसंचार कंपनियों ने इस निर्णय के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की थी, लेकिन उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। तब तीन दूरसंचार कंपनियां फिर से सर्वोच्च न्यायालय की शरण में पहुंच गईं और संशोधन याचिका दाखिल की थी जिस पर इस सप्ताह सुनवाई होनी है।

इस बीच तीन दूरसंचार कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को भी अलग अलग पत्र भेजे हैं जिनमें कहा गया है कि वे अपने बकाया का भुगतान करना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का इंतजार करेंगी। इस भुगतान के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 23 जनवरी की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।

हालांकि आशंका जताई जा रही है कि भुगतान न करने की वजह से सरकार इन दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जिसमें बैंक गारंटी भुनाने या इस संबंध में कारण बताओ नोटिस भेजने की प्रक्रिया शामिल हो सकती है।

मारुति ने चुनिंदा मॉडलों के दाम 10,000 रुपये तक बढ़ाए

कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया (एमएसआई) ने अपने कुछ मॉडल के दाम तत्काल प्रभाव से 10,000 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने कच्चे माल की बढ़ी लागत की भरपाई के लिए यह कदम उठाया है। एमएसआई ने सोमवार को एक बयान में कहा कि विभिन्न मॉडल की कीमत में बढ़ोतरी अलग-अलग हुई है। इसमें दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 4.7 फीसदी तक बढ़ाई गई है। नए दाम 27 जनवरी 2020 से प्रभाव में आ गए हैं। ऑल्टो मॉडल के दाम में 6,000 से 9,000 रुपये, एस प्रेसो के दाम में 1,500 से 8,000 रुपये, वैगन आर में 1,500 से 4,000 रुपये तक की वृद्धि हुई है। [illegible] ने बहुद्देश्यीय वा[illegible] 4,000 से [illegible] 3,0[illegible]

इंडिया डेडिकेटेड फंडों से 5.4 अरब डॉलर की निकासी

ईपीएफआर का भारत में प्रवाह

	भारत-केंद्रित	जीईएम	अन्य
दिसंबर	-950	628	-41.0
3-महीने	-1891	1095	-12.0
6-महीने	-3227	-56	-466.0
कैलेंडर वर्ष 19	-5391	1268.0	-1175.0

स्रोतः ईपीएफआर, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (डॉलर मिलियन में)

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 27 जनवरी

दिसंबर में इंडिया डेडिकेटेड फंडों से 95 करोड़ डॉलर की निकासी हुई, जिसके बाद कैलेंडर वर्ष 2019 में ऐसे फंडों से कुल निकासी 5.4 अरब डॉलर पर पहुंच गई। कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्विटी की तरफ से संकलित ईपीएफआर डेटा से यह जानकारी मिली।

ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड (जीईएम) ने 62.8 करोड़ डॉलर की निकासी का सामना किया और साल 2019 में कुल निकासी करीब 1.2 अरब डॉलर पर पहुंच गई। इंडिया डेडिकेटेड, जीईएम और अन्य श्रेणी के फंडों से अगस्त में कुल 36.3 करोड़ डॉलर की निकासी हुई थी और कैलेंडर वर्ष में 5.3 अरब डॉलर।

इंडिया डेडिकेटेड फंडों की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) पिछले साल 3.6 फीसदी घटकर 44.2 अरब डॉलर रह गई। इसकी तुलना में जीईएम का एयूएम 6.8 फीसदी की उछाल के साथ 81.5 अरब डॉलर रहा।

ईपीएफआर फंड मूल रूप से म्युचुअल फंडों, ईटीएफ, क्लोज एंड फंड, वैरिएबल एन्युटी फंड और बीमा से जुड़ाव वाले फंडों को ट्रैक करता है। इसमें हेज फंडों, प्रोप्राइटरी डेस्क और सॉवरिन वेल्थ फंडों की तरफ से हुए निवेश शामिल नहीं हैं, जिस पर एनएसडीएल नजर रखता है।

एशियाई फंडों (जापान को छोड़कर) की तरफ से भारत को कुल आवंटन नवंबर के 13.1 फीसदी के मुकाबले दिसंबर में 12.6 फीसदी घटा, वहीं जीईएम फंड नवंबर के 9.8 फीसदी से घटकर 9.3 फीसदी रह गया।

वित्तीय क्षेत्र में दिसंबर में भारी खरीदारी हुई और कुल 71.1 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ जबकि सूचना प्रौद्योगिकी में 68.7 करोड़ डॉलर। माह के दौरान दूरसंचार से सबसे ज्यादा 21 करोड़ डॉलर की निकासी हुई।

दिसंबर में भारतीय बाजार 1.1 फीसदी चढ़े जबकि साल 2019 में 14.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

को-लिविंग स्पेस में आ रही ब्रुकफील्ड

राघवेंद्र कामत और अनीश फडणीस
मुंबई, 27 जनवरी

कनाडा की संपत्ति प्रबंधन कंपनी ब्रुकफील्ड नए ब्रान्ड के साथ को-लिविंग स्पेस क्षेत्र में कदम रखने जा रही है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। को-लिविंग इस समय पूरी दुनिया में जगह बना रही है, जहां तमाम लोग एक आवास साझा करते हैं।

सूत्रों ने बताया कि अंधेरी ईस्ट में आईटीसी होटल के नजदीक हवाईअड्डे की 15 एकड़ जमीन के लिए ब्रुकफील्ड मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट (मायल) के साथ बातचीत कर रही है, जो अंतिम चरण में है। सूत्रों ने कहा कि को-लिविंग प्रॉपर्टी के अलावा निवेशक प्लॉट पर वाणिज्यिक संपत्ति की भी योजना बना रही है।

सूत्रों ने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि ब्रुकफील्ड शुरुआत में कुछ पैसे का भुगतान करेगी और शेष भुगतान मायल के साथ राजस्व साझा के आधार पर होगा।

सूत्रों ने कहा, 'यह ब्रुकफील्ड के लिए नया क्षेत्र है। वह भारत में इस क्षेत्र में कारोबार की व्यापक संभावना देख रही है। अन्य शहरों में भी व इसी तरह की को-लिविंग प्रॉपर्टी इसी ब्रान्ड के तहत विकसित कर सकती है।' उन्होंने कहा कि वह जमीन खरीदने या पट्टे पर लेने के लिए अन्य डेवलपरों से भी बात कर रही है। इस मसले पर ब्रुकफील्ड ने प्रतिक्रिया देने से इनकार किया, वहीं मायल को भेजे गए मेल का कोई उचित जवाब नहीं मिला। ब्रुकफील्ड की मुंबई व अन्य शहरों में 2.5 करोड़ वर्गफुट वाणिज्यिक संपत्तियां हैं। उसने पिछले साल 3,950 करोड़ रुपये में लीला होटल की संपत्तियां खरीदी थीं।

ब्रुकफील्ड ने यूनिटेक कॉर्पोरेट पार्क की की संपत्तियां एनसीआर और कोलकाता में तथा मुंबई के पवई इलाके में हीरानंदानी परिवार की वाणिज्यिक संपत्तियों में हिस्सेदारी खरीदी थी। उसने आवासीय संपत्तियों में केवल कर्ज समझौते किए हैं। कंपनी ने ऋण सौदों के माध्यम से आवासीय रियल एस्टेट में 1 अरब डॉलर निवेश की योजना बनाई है। कई रियल एस्टेट कंपनियां इस क्षेत्र में उतर रही हैं। हाल ही में बेंगलूरु की एंबेसी ने घोषणा की है कि वह 2,000 करोड़ रुपये निवेश कर ऑलिव बॉन्ड के तहत देश के 6 प्रमुख शहरों में को-लिविंग स्पेस विकसित करेगी। कंपनी ने इस साल बेंगलूरु और चेन्नई में 2,500-2,500 बेड के दो केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। बेंगलूरु की पूर्वांकरा ने मुंबई के गोरेगांव में को लिविंग स्पेस का केंद्र बनाने की योजना बनाएगी, जो करीब 3,50,000 वर्गफुट में होगा।

वहीं लोढ़ा समूह के प्रबंध निदेशक अभिषेक लोढ़ा और गोदरेज प्रॉपर्टीज के कार्यकारी चेयरमैन पिरोजशा गोजरेज ने को-लिविंग स्टार्टअप पोसुर में पिछले साल निवेश किया है। बेंगलूरु की स्टार्टअप कोलिव ने रियल एस्टेट कंपनी सालारपुरिया सत्व से 92 लाख डॉलर जुटाए हैं। कुशमैन वेकफील्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बाजार का आकार 2019 के 6.6 अरब डॉलर से दोगुना होकर 2025 में 14 अरब डॉलर होने की संभावना है। को-लिविंग कंपनियों को इसलिए लुभा रहे हैं क्योंकि इसमें 8 से 11 प्रतिशत तक का मुनाफा है, जबकि इसकी तुलना में आवासीय संपत्तियों में 1 से 3 प्रतिशत यील्ड रह गया है। दिलचस्प है कि को लिविंग स्टार्टअप जैसे ओयो लाइफ, नेस्टावे का द हेलो वर्ल्ड, जोलो, गेस्टर सक्रियता से इस क्षेत्र में अवसर तलाश रहे हैं।

रियल एस्टेट क्षेत्र में ब्रुकफील्ड के कदम

को-लिविंग के लिए अंधेरी ईस्ट में 15 एकड़ जमीन पट्टे पर लेने के लिए मायल से चल रही है कनाडा की संपत्ति प्रबंधन कंपनी ब्रुकफील्ड की बात

- मुंबई, एनसीआर और कोलकाता में **2.5** करोड़ वर्गफुट वाणिज्यिक संपत्तियां
- **2014** में **2,023** करोड़ रुपये में खरीदा यूनिटेक कॉर्पोरेट पार्क
- **2016** में हीरानंदानी के प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो में खरीदी **45** लाख वर्गफुट जगह
- **2019** में **3,950** करोड़ रुपये में खरीदी होटल लीला की संपत्तियां
- आवासीय संपत्तियों में **1** अरब डॉलर के ऋण सौदे की योजना

सेबी के नए प्रमुख की तलाश शुरू

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 27 जनवरी

केंद्र सरकार ने आज भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन पद पर अजय त्यागी का स्थान लेने वाले उम्मीदवार की तलाश आरंभ कर दी। त्यागी का कार्यकाल 1 मार्च को समाप्त हो रहा है। वित्त मंत्रालय ने इस पद पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन दिया है और आवेदन करने के लिए केवल दो सप्ताह का समय दिया है जबकि सामान्यत: इसके लिए तीन महीने का समय दिया जाता रहा है। नियामक के कार्यकाल को एक बार फिर से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जा रहा है।

मंत्रालय की ओर से जारी किए गए विज्ञापन में दिए गए पात्रता मानकों के मुताबिक इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति का कार्यकाल पांच वर्ष और 65 वर्ष की उम्र से अधिक जो भी पहले हो, तक होगा। वह व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होगा।

त्यागी ने 1 मार्च, 2017 को इस पद पर यू के सिन्हा से पदभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल पांच वर्ष तय किया गया था जिसे बाद में घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया था।

सेबी प्रमुख को 4.5 लाख रुपये मासिक का समेकित वेतन दिया जाएगा। इस पद के लिए आवेदन 10 फरवरी तक किया जा सकता है। प्रतिभूति बाजार और संबंधित क्षेत्रों का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा उसके पास 25 वर्षों का पेशेवर अनुभव होना चाहिए।

एनसीएलटी देगा कंपनियों में नियुक्त सदस्यों को संरक्षण

अमृता पिल्लई
मुंबई, 27 जनवरी

राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) के एक निर्णय से आईएलऐंडएफएस समूह को अपने अधीनस्थ स्तर के बोर्ड में रिक्तियों को भरने में मदद मिल सकती है। अधिकरण ने यह स्पष्ट किया है कि वह समूह के विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में बोर्ड की ओर से तय सदस्यों को अपना संरक्षण प्रदान करेगा।

एनसीएलटी ने अपने संरक्षण के दायरे को और अधिक विस्तारित करने का आदेश दिया है जो पहले केवल सरकार की ओर से नियुक्त बोर्ड सदस्यों तक ही सीमित था।

आदेश में कहा गया है, 'हम स्पष्ट करते हैं कि इस न्यायालय की ओर दिए गए संरक्षण में केवल यहां से नियुक्त किए निदेशक ही शामिल नहीं होंगे बल्कि इसके दायरे में उन निदेशकों को भी शामिल किया जाता है जिनकी नियुक्ति आईएलऐंडएफएस बोर्ड अनुषंगी, अन्य समूह कंपनियों और आईएलऐंडएफएस एंप्लोइज वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टियों के लिए करेगा।'

इससे पहले के आदेश में संरक्षण एनसीएलटी की ओर से नियुक्त निदेशकों को ही दी गई थी जिसे नया बोर्ड का नाम दिया गया था। नए बोर्ड में उदय कोटक, विनीत नायर, सीएस राजन, जीएन वाजपेयी, जी सी चतुर्वेदी, मालिनी शंकर, नंद किशोर, विजय कुमार और एन श्रीनिवासन शामिल हैं। आईएलऐंडएफएस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा, 'एनसीएलटी ने निर्देश दिया कि उसकी पूर्व मंजूरी के बिना निलंबित निदेशकों की पिछली कार्रवाइयों और गलतियों के लिए नए बोर्ड के खिलाफ कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए और नए बोर्ड के निदेशकों को अभयदान दिया।' यह संरक्षण अब नए बोर्ड की ओर से नियुक्त किए गए सभी बोर्ड निदेशकों और नामित सदस्यों को दी जाएगी। इस मामले के प्रत्यक्ष जानकार एक व्यक्ति ने अपनी पहचान जाहिर नहीं करने की इच्छा जताते हुए कहा, 'अब तक संरक्षण केवल सरकार की ओर से नियुक्त बोर्ड सदस्यों को ही मिलती थी। इस फैसले से आईएलऐंडएफएस समूह की सभी कंपनियों के पेशेवरों और स्वतंत्र बोर्ड सदस्यों में एक असुरक्षा का भाव भर गया था और निर्णय प्रक्रिया बाधित हुई थी।'

अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में आईएलऐंडएफएस समूह ने कहा, 'रेखांकित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन, कुछ कंपनियों के बोर्ड में निदेशकों की अनुचित संख्या, वैधानिक अंकेक्षकों की अनियत रिक्तियों और लेखा जांच से गुजर चुके वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने और स्वीकार करने की बढ़ी हुई समय सीमा के संदर्भ में संबंधित अनुषंगी कंपनियां चुनौतियों का सामना कर रही हैं।'

उक्त व्यक्ति ने कहा कि एनसीएलटी के ताजा आदेश से कपंनियों के लिए बेहतर समाधान का रास्ता सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा, 'निदेशकों की संख्या अपर्याप्त होने से अनुपालन की चुनौतियां उभर रही हैं और कंपनियों के समाधान में रुकावट आ रही है।'

ब्राजील ने उद्योगों के लिए खोले द्वार

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 27 जनवरी

ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोलसोनारो ने लैटिन अमेरिकी देश में बुनियादी ढांचे, रेलवे, खनन और ऊर्जा क्षेत्रों में भारत की दिग्गज कंपनियों को निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है।

बोलसोनारो ने ब्राजील के वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में उद्योग के दिग्गजों को संबोधित करते हुए भारत से ज्यादा निवेश किए जाने की वकालत की। ब्राजील की अर्थव्यवस्था के 2020 में गति पकड़ने की उम्मीद है और वहां के केंद्रीय बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

गरीबी उन्मूलन और भ्रष्टाचार के खात्मे का नारा देकर ब्राजील में लोकप्रियता हासिल करने वाले बोलसोनारो देश में बड़े पैमाने पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश की बात कही। उन्होंने खासकर एमेजॉन रेनफॉरेस्ट पर जोर दिया, जो दूर दूर फैली आबादी में मौजूद है। भारत की कंपनियों ने करीब 6 अरब डॉलर निवेश किया है और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अहम उपस्थिति है।

इन कंपनियों में सूचना तकनीक क्षेत्र की दिग्गज जैसे टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रमुख हैं, जिनके करीब 1,400 कर्मचारी हैं। खनन के क्षेत्र में स्टरलाइट पावर ने ब्राजील के 11 राज्यों में 10 पारेषण परियोजनाएं और 34 सबस्टेशन हासिल किए हैं। वहीं विश्व की सबसे बड़ी कॉर्बन ब्लैक प्रोड्यूसर बिड़ला कार्बन ने अक्टूबर 2018 में ब्राजील में अपने परिचालन के 60 साल पूरे किए हैं।

दवा, ऊर्जा, इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल उत्पादन क्षेत्र भी भारत के कारोबारियों की दिलचस्पी के प्रमुख क्षेत्र हैं। नीति निर्माताओं का कहना है कि तेल व प्राकृतिक गैस और बॉयोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सप्ताहांत में हुए समझौते से भारत के कारोबारियों के ब्राजील में प्रवेश की अहम संभावना है।

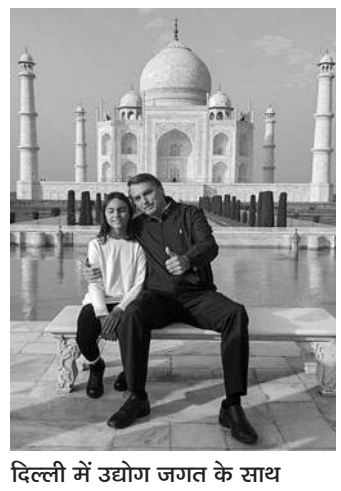

दिल्ली में उद्योग जगत के साथ बातचीत के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोलसोनारो सोमवार को आगरा में ताजमहल देखने भी गए, जहां उन्होंने अपनी बेटी के साथ तस्वीर खिंचाई *-पीटीआई*

बोलसोनारो ने उद्योग जगत के 23 दिग्गजों से मुलाकात की, जिनमें स्टरलाइट पावर, अपोलो हॉस्पिटल, ओयो रूम्स, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जाइडस कैडिला और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आफ इंडिया सहित अन्य कंपनियों से जुड़े लोग शामिल रहे।

निर्यात पर ध्यान

बहरहाल भारत को उम्मीद है कि वह ब्राजील के माध्यम से लैटिन अमेरिकी देशों में निर्यात बढ़ा सकता है, जहां पहुंचना मुश्किल है। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 2022 तक 15 अरब डॉलर हो सकता है। दोनों देश भारत, मरकोसर प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (पीटीए) को विस्तार देने पर काम कर रहे हैं, जिसमें दोनों देश शामिल हैं।

बहरहाल 2018-19 में लगातार तीसरे साल ब्राजील को निर्यात बढ़कर 3.8 अरब डॉलर पहुंच गया है। वहीं आयात घटकर 5.4 अरब डॉलर रह गया है, जिसमें एक साल में एक अरब डॉलर की कमी आई है।

जुलाई के मध्य में भारत ने ब्राजील से कहा था कि वह नई दिल्ली के साथ पीटीए को लेकर लैटिन अमेरिकी आर्थिक ब्लॉक के देशों के साथ बातचीत में तेजी लाए, जिसमें अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे शामिल हैं। पीटीए पर 2004 में समझौता हुआ था और यह इस महाद्वीप के व्यापक उपभोक्ता बाजार में पहुंचने का एकमात्र साधन है।

यूपीआई में गूगल पे का हिस्सा 49 प्रतिशत

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 27 जनवरी

फिनटेक फर्म रेजरपे की रिपोर्ट 'द इरा आफ राइजिंग फिनटेक' के मुताबिक 2019 में डिजिटल लेन देन में यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ऐप में गूगल पे की हिस्सेदारी 59 प्रतिशत, वॉलमार्ट के फोन पे की 26 प्रतिशत, पेटीएम की 7 प्रतिशत और भीम की 6 प्रतिशत रही है।

रिपोर्ट में भारत में तेजी से बढ़ते फिनटेक के कारोबार, डिजिटल लेन देने के तरीकों व यूपीआई जैसे नवोन्मेष के असर के बारे में गहराई से अध्ययन किया गया है।

2018 में गूगल पे की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत और भीम की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत थी। उसके बाद फोन पे की 15 प्रतिशत और पेटीएम की हिस्सेदारी 4 प्रतिशत थी। इसके अलावा 2019 में एमेजॉन पे ग्राहकों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला वॉलेट (36 प्रतिशत) है, उसके बाद ओला मनी (17 प्रतिशत) आता है।

2019 में कार्ड का इस्तेमाल (33 प्रतिशत) व नेटबैंकिंग (11 प्रतिशत) कम हुआ है, 2018 में यह क्रमश: 56 प्रतिशत और 23 प्रतिशत पर थे। यूपीआई का इस्तेमाल 2018 के 17 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 38 प्रतिशत हो गया है। रेजरपे के सहसंस्थापक और सीईओ हर्षिल माथुर ने कहा, '2018-19 में डिजिटल भुगतान में 338 प्रतिशत की बढ़ोतरी जोरदार है। यह अब तक की सबसे तेज बढ़ोतरी है। यूपीआई का महत्त्व बढ़ने से भी ऑनलाइन का दबदबा बढ़ा है।'

बीएस सूडोकू 3649

	2	6	4				1	
3		8						
	5		7				6	9
	1			4				
9		2	6		8	7		5
				2			8	
6	8				4		9	
						8		4
	4				9	1	7	

परिणाम संख्या 3648

5	3	4	7	1	6	9	8	2
9	8	2	4	5	3	1	6	7
6	7	1	8	9	2	4	3	5
1	6	7	2	3	4	5	9	8
8	9	3	1	7	5	2	4	6
2	4	5	6	8	9	7	1	3
3	5	6	9	4	7	8	2	1
4	2	8	5	6	1	3	7	9
7	1	9	3	2	8	6	5	4

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मुश्किल
★★★★☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2000/2010, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4250/4300, तिल सफेद 8700/8800, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1450/1550,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2000/2010, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4300/4400, लालमती 3200/3250, चावल (सोना) 2800/2850,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1395, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1475, फ्लैक 1420, डीएमओ 1000, टरपीन लैस बोल्ड 1505

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1100/1200, खुरपा 1030/1045,चाकू 1020/1100, रसकट 840/860, शक्कर 1200/1220, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3315, सिहोरा 3300, बुंदकी 3260, बुढ़ाना 3325,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3500/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 990/1000, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4300, खल: सरसों 2100/2150, बिनौला 2300/2400, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5300/5400, गेहूं (मिल) 2080/2100, मक्की 2125/2130, बाजरा 1800/1810, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3750/3800, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4440/4450,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2100, ग्वार 3700/3750, जौ 2100/2125,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4050/4100, ग्वारगम 7300/7350, बाजरा (गुजरात) 1800/1825, बाजरा (जयपुर) 1825/1835, चना 4100/4200, काबली चना 5000/6000, मूंग 7100/7300,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)128, राइसब्रान (अखाद्य) 125, खल सरसों 1930, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1200, लाल 1200, कंटीन्यूअस 1250,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7800/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7400/8400, उड़द धोया 9000/9800, छिलका 8700/9300, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5400/5500,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 5900/6000, सेला 5400/5425, शरबती साधारण सेला 3700/3750, शरबती स्टीम 4100/4150,चावल 1509 सेला 5050/5100, धान: शरबती 2050/2100,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4100/4130, हरियाणा 4060/4080, राजस्थान 4000/4070, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2350/2450, सरसों खल 2040/2050,

फाजिल्का
गेहूं 2040/2050, सरसों 4200/4250 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4100/4130, कपास देशी 5100/5200, कपास नरमा (क्विं.) 5200/5300, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2400/2500,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2000/2040, चावल परमल कच्चा 2350/2400, से ला 2300/2350, मक्की यूपी 2100/2120, दाल उड़द छिलका 8600/9700, चना देशी 4700/4750, दाल चना 5100/5150, काबली चना 5200/6100, राजमां चित्रा पुणे 7100/8500, चीन 8000/8400, शर्मिली 6000/7000,

करनाल
गेहूं दड़ा 2000/2025, बासमती चावल 6300/6400, धान 1121 नं. 2925/2975, पूसा 1509 धान 2850/2875, शरबती धान 2100/2150, सेला (1509 नं.) चावल 5050/5100, स्टीम 5900/6000,

हिसार
ग्वार 3775/3800, जौ 1840/1850, सरसों 3900/3950, मूंग 6900/7000, गेहूं 2050/2065,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2150/2180, आटा (प्रति 44 किलो) 1040/1060, मैदा 1160/1180, देशी घी (एक ली/जार) 380/500, रिफाइंड (टीन) 1500/1550,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4050/4100, खल बिनौला मोटी 2300/2400, बिनौला 2700/3200, सरसों तेल 9050/9100, गेहूं 2100/2125, ग्वार 3850/3900, बाजरा 1800/1850 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 293

कम न हो हस्तांतरण

हाल के दशकों में राज्य सरकारों के संचालन से जुड़ी जवाबदेहियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य सरकारों को जो सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और जो वे प्रदान कर सकती हैं उन पर अधिक राजनीतिक जोर दिया जाने लगा है। जाहिर है इसे राज्य सरकारों को मिलने वाली कर हिस्सेदारी में बढ़ोतरी से जोड़कर देखा जाता है। कर ही देश और उसके नागरिकों के बीच जुड़ाव का प्राथमिक जरिया है। जानकारी के मुताबिक 15वें वित्त आयोग के माध्यम से इस परिपाटी को उलटा जा रहा है।

इस समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकारों के व्यय के लिए अलग किया जाने वाला टैक्स पूल का 42 फीसदी हिस्सा वास्तव में कम किया जा सकता है। इसमें बांटने वाले पूल में किसी तरह के बदलाव को शामिल नहीं किया गया है। वित्त आयोग की शर्तों में बाद में हुए बदलाव के आधार पर आगे चलकर इसमें भी परिवर्तन कर सकता है। उक्त बदलाव के अनुसार राष्ट्रीय संसाधनों पर रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं का अलग से दावा होने की बात कही गई है।

चूंकि रक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है इसलिए आयोग द्वारा ऐसा करने से यकीनन बांटने लायक पूल में कमी आएगी। यदि राज्यों के एकीकृत हस्तांतरण में कमी के साथ मिलाकर देखें तो यह राशि बहुत ज्यादा होगी और इसके अभाव में राज्यों की जरूरी सेवाएं मुहैया कराने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। हमें इस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आयोग जहां यह दावा कर सकता है कि केंद्र सरकार की खास योजनाओं और पहलों के लिए पहले से आवंटित धन में दावेदारी करके इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। परंतु यह पर्याप्त नहीं होगा। राज्य सरकारें लोगों को जरूरी सेवाएं मुहैया कराने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं। उनके पास यह अधिकार होना चाहिए कि वे जरूरी संसाधन अपने पास रहते हुए शासन संबंधी निर्णय ले सकें। हाल के दशकों में देश की राजनीति कमोबेश इसी दिशा में आगे बढ़ी है। राज्य स्तर के राजनेताओं से उनके मतदाता यही अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें जरूरी सेवाएं मुहैया कराएंगे और यह अपेक्षा गलत भी नहीं है। जाहिर है राज्य सरकारों को मुहैया कराए जाने वाले संसाधनों में यह लोकतांत्रिक गतिशीलता नजर आनी चाहिए।

इसमें दो राय नहीं कि केंद्र सरकार कहेगी कि उसके पास खुद संसाधनों की कमी है। खासतौर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसा हुआ है। परंतु इसके लिए वह किसी और को दोष नहीं दे सकती। अर्थव्यवस्था के आकार में इजाफा उसकी जवाबदेही है और कर संग्रह में कमी आने की एक अहम वजह आर्थिक वृद्धि में आया ठहराव भी है।

राज्य भी जीएसटी को लेकर शिकायत कर सकते हैं। वे कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ अप्रत्यक्ष कर जुटाने की अपनी शक्तियां केंद्र को सौंप दीं और हस्तांतरणीय कर पूल में कमी करके तो उन्हें पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है।

देश की आम राजनीतिक परिस्थितियों पर गौर करना भी आवश्यक है। हाल के वर्षों में देश के संघीय ढांचे को लेकर कई तरह के तनाव उभरे हैं। कई राज्य सरकारों द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के प्रति अनिच्छा इसका केवल एक उदाहरण है। अन्य उदाहरणों की बात करें तो अलग-अलग जनांकीय दबाव और देश के भौगोलिक क्षेत्र में सापेक्षिक राजनीतिक शक्ति में बदलाव भी हमारे सामने हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन आवंटित करने की दशकों लंबी गतिशील प्रक्रिया में बदलाव करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। इसे समझदारी नहीं माना जा सकता है।

अजय मोहंती

ब्रांड भारत और ब्रांड मोदी को झटका

आर्थिक पराभव और पहचान आधारित राजनीति ने ब्रांड भारत और ब्रांड मोदी दोनों को नुकसान पहुंचाया है।

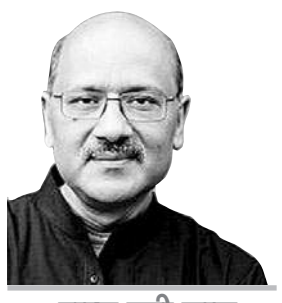

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

क्या दुनिया हमेशा भारत को नीचा दिखाने के षडयंत्र में लगी रहती है? क्या बड़ी ताकतें, खासतौर पर पश्चिम के लोकतांत्रिक देश भारत के उभार से आशंकित हैं? पिछले कुछ समय से सरकार के प्रति आस्था रखने वालों में एक जुमला चल रहा है- हिंदू भारत के उदय के खिलाफ ईसाई-इस्लामिक षडयंत्र का जुमला। क्या शेष विश्व भारत तथा अन्य देशों मसलन चीन आदि के साथ अलग-अलग व्यवहार करते हैं?

उपरोक्त में से अंतिम को छोड़कर सारी बातें गलत हैं। अंतिम बात इसलिए सच है क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था का आकार हमसे बहुत बड़ा है। सच तो यह है कि अब तक के सात दशक में तमाम विश्व भारत की सफलता की कामना करता रहा है।

पाकिस्तान और चीन जैसे पारंपरिक शत्रुओं को छोड़ दिया जाए तो ऐसे देश का नाम लेना मुश्किल है जिसने भारत का भला न चाहा हो या जिसे भारत की नाकामी से लाभ हुआ हो। यह इस तथ्य के बावजूद है कि हम हर दशक में अपने बारे में अपेक्षाएं मजबूत करने और फिर न केवल खुद को बल्कि अपने वैश्विक प्रशंसकों तक को नीचा दिखाने की आदत सी डाल चुके हैं।

देश की आर्थिक प्रगति में आया ठहराव एक झटका है। बहरहाल, बड़ी दिक्कत यह है कि सामाजिक संकेतकों पर पिछड़ने, लोकतंत्र की रैंकिंग में गिरावट, भ्रष्टाचार में इजाफा, सीएए/एनआरसी को लेकर शांतिपूर्ण देशव्यापी प्रदर्शनों और सत्ता की ओर से आक्रामक,भेदभावपूर्ण और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के कारण आदि के कारण हमारा नैतिक कद घटा है।

शीतयुद्ध के बाद के तीन दशक में दावोस बैठकों में भारत भले ही पसंदीदा रहा हो या नहीं लेकिन उससे अपेक्षाएं की गईं। वह जिस प्रकार अपनी विविधता के साथ बढ़ता रहा, जिस लोकतांत्रिक ढंग से वहां सत्ता परिवर्तन हुआ, उसने अपनी सोच को आर्थिक और सामरिक दृष्टि से वैश्वीकृत किया। इन तीन दशकों में दुनिया के सामने कई बड़े संकट आए क्योंकि दुनिया के बाकी हिस्से यह सिलसिला दोहरा नहीं सके। बाल्कन देशों से लेकर पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक इसके उदाहरण बिखरे हुए हैं।

सन 1991 के बाद के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और ब्रांड इंडिया मजबूत हुआ। दुनिया अचरज में थी कि यह अराजक देश तो साल दर साल सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्थिर होता जा रहा है और वैश्विक वृद्धि का वाहक बन गया है। चीन भारत से आगे था लेकिन वहां अधिनायकवादी शासन था। उसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था ऐसी थी जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता था। पुतिन या ईरान के आयतुल्लाह तक नहीं। भारत इसके उलट था। यह पूरी दुनिया के सामने उदाहरण था कि कैसे बड़ा, विविधतापूर्ण देश लोकतांत्रिक तरीके से बल्कि लोकतंत्र के कारण आगे बढ़ रहा है। कल्पना कीजिए कि अगर भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के पास उदार, लोकतांत्रिक, समावेशी राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति नहीं होती तो उसका क्या होता?

यह सोवियत संघ, युगोस्लाविया या पश्चिमी एशिया की तरह खंड-खंड हो सकता था या रूस, तुर्की अथवा चीन की तरह अधिनायकवादी हो सकता था। तेजी से विकसित होता हुआ, सुरक्षित और स्थिर भारत अपनी गरीबी, विविधता और लाखों समस्याओं के बावजूद लोकतंत्र और उदारवाद का मूल्यवान वाहक था।

अब यह खतरे में है। भारत के दशकों पुराने दोस्त और प्रशंसक अब उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। अक्सर यह सवाल सुनने को मिलता है कि भारत में चल क्या रहा है? क्या हालात और खराब होने वाले हैं? आप यहां तक पहुंचे कैसे? कोई विदेशी शक्ति, चाहे वह राजनीतिक हो या कॉर्पोरेट या नेता, वह भारत में आए इस ठहराव का जश्न नहीं मना रही। लेकिन हमारे मित्रों को लग रहा है कि कुछ तो दिक्कत है।

हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं जिसे महानता से गिरावट की संज्ञा दी जा सके। इसलिए क्योंकि हमारे मित्र भी निहायत आशावादी हैं। उन्हें यकीन है कि तमाम झटकों के रूप में भारत का विचार कायम रहेगा। उन्हें इस बात से राहत मिलती है कि देश के कुछ बड़े संस्थान, कभी न्यायपालिका तो कभी मीडिया प्रतिरोध करते हैं। महिलाओं, युवाओं और मुस्लिमों का व्यापक प्रतिरोध आशा जगाता है। संदेश यही है कि हमारे यहां समस्या है। लेकिन दुनिया का दूसरा कौन सा देश होगा जहां इस स्थिति में भी पुरुष और स्त्रियां, मुस्लिम और हिंदू सड़कों पर एकत्रित होकर संविधान की प्रस्तावना का पाठ करते होंगे।

इसका एक अतिराष्ट्रवादी प्रतिरोध यह होगा कि यदि आप अपने जैसे लोगों से ही बात करेंगे जो आपकी तरह भ्रमित, वाम-उदारवादी हैं तो भला आप और क्या सुनेंगे? वे तो देश में पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई दक्षिणपंथी हिंदू सरकार को लेकर अवमानना का भाव ही रखेंगे।

दो बातें समझने की आवश्यकता है। पहला, इस श्रेणी के लोग पारंपरिक रूप से सबसे बड़े भारत प्रेमी रहे हैं। सन 1991 के बाद देश के उदय की सराहना करने वालों में भी वे अव्वल रहे हैं और पाकिस्तान जनित आतंकवाद का विरोध करने वालों में भी। इन दशकों में उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक सरदर्द, जिहाद की पाठशाला और एक परेशान करने वाला देश ही माना है।

आज जब इमरान खान भारत की तुलना सन 1930 के दशक के नाजी जर्मनी से करते हैं तो ये खामोशी से देखते रहते हैं। वे सहमत नहीं हैं, न ही वे इसे सच होते देखना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि भारत का बचाव कैसे किया जाए? वे अकादमिक लोगों और पत्रकारों को वीजा मिलने की समस्या की बात करते हैं, मीडिया पर दबाव की बात करते हैं और पूछते हैं कि भारत चीन की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है?

दूसरा ये संदेह केवल बौद्धिकों, नीति जगत और मीडिया के मन में नहीं हैं। वैश्विक कारोबारी जगत भी चिंतित है। नीतिगत स्थिरता गायब हो चुकी है। नए कर और नियमन देखने को मिल रहे हैं। कर एवं नियामकीय प्रक्रियाओं और सबसे बढ़कर न्यायपालिका में अव्यवस्था देखने को मिली और अब आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी, छोटे व्यापारियों के बचाव को लेकर पुरानी समाजवादी व्यवस्था की वापसी नजर आ रही है। सबसे बढ़कर आपके मंत्री हमें फटकारते हैं। संक्षेप में कहें तो भारत एक चिड़चिड़े राष्ट्र में बदल रहा है। यह उन्हें पसंद नहीं।

अगले कदम में शायद हम एक सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर बनने की ओर बढ़ जाएंगे। कहा जाएगा कि सन 2014 के बाद एक नया इतिहास शुरू हुआ है और यह भारत दूसरों को खुश करने के लिए पीछे नहीं हटता। यहां फिर दो समस्याएं सामने हैं।

पहली बात, यह बदलाव तभी हो सकता है जब आपने वैसी हार्ड पावर अर्जित की हो। अंतरराष्ट्रीय सामरिक जगत की समझ रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत निर्णायक प्रतिकार करने का हौसला रखता है लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान जैसे छोटे से देश को दंडित न कर पाने की हमारी कमजोरी भी उजागर हो गई। ऐसे में खुद को हार्ड पावर जताना अपरिपक्वता है।

दूसरा, मार्केटिंग की दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा कि राष्ट्रों समेत तमाम ब्रांड की अपनी खासियत होती है। चीन के मामले में यह है सख्त, बेलागलपेट, सक्षम शासन, जातीय समरसता, सैन्य शक्ति और हर वर्ष दुनिया में सर्वाधिक लोगों को मृत्यु दंड देते हुए भी इसे गोपनीय बनाए रखना।

पाकिस्तान जो इन दिनों हमारा पसंदीदा संदर्भ बिंदु है, उसके बारे में तो बात न ही करें तो बेहतर है। भारत का बुनियादी ब्रांड मूल्य है लोकतंत्र, विविधतापूर्ण जीवन की सहजता, समावेशी शासन, तर्कपूर्ण और विचारपूर्ण समाज। भारत किसी भी दृष्टि से नरम राज्य नहीं है। अगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत इकलौते बड़े, विविधतापूर्ण देश के रूप में उभरा है जो अक्षुण्ण है और लगातार मजबूत हुआ है तो ऐसा हो भी नहीं सकता। तमाम अन्य देश मसलन सोवियत संघ से पाकिस्तान तक, चाहे जितने सख्त रहे हों, वे टूट गए। हमें इसे भारत के प्रति, खासकर हिंदुत्व के प्रति पश्चिम का पूर्वग्रह कहकर खारिज कर सकते हैं। इससे यह हकीकत नहीं बदलेगी कि पहचान की राजनीति और आर्थिक पराभव ने एक ब्रांड के रूप में भारत को नुकसान पहुंचाया है। इसका असर ब्रांड मोदी पर भी पड़ा है। हमें गहरी सांस लेकर सुधार शुरू करने की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं कि हमें परवाह नहीं लेकिन 4.8 फीसदी की वृद्धि दर और 45 वर्ष की उच्चतम बेरोजगारी दर पर यह जवाब सही नहीं।

राजस्थान एवं गुजरात में टिड्डियों के हमले का कारण जलवायु परिवर्तन

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयंकर आग का कारण जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। इस आग से वहां की जमीन बुरी तरह झुलस गई तथा कई लोग और जंगली जानवर मारे गए हैं। वहां के जंगलों में आग लगना सामान्य है लेकिन इस भयानक आग का कारण यह था कि गर्मी का स्तर बढ़ रहा है। इस वजह से वहां मैदान सूख गए और स्थिति विकराल हो गई। लंबे समय से पड़ रहे सूखे के कारण वहां आग के लिए आदर्श स्थिति बन गई। लेकिन दुनिया का ध्यान ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग की तरफ था और दूसरी ओर हमारे यहां इससे भी बदतर मानवीय संकट पैदा हो गया। इसका संबंध भी जलवायु परिवर्तन से है।

दिसंबर में टिड्डियों के भारी भरकम झुंडों ने राजस्थान और गुजरात में फसलों को चौपट कर किसानों की आजीविका को बरबाद कर दिया। इससे फसलों को हुए नुकसान के बारे में अभी तक ज्यादा अनुमान नहीं है लेकिन सरकारों ने दिल्ली के आकार से लगभग तीन गुना अधिक क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव किया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग की तरह यह दलील दी जा सकती है कि इस क्षेत्र में टिड्डियों का हमला आम है तो फिर से हंगामा क्यों?

'डाउन टु अर्थ' पत्रिका में मेरे सहयोगियों ने अपनी जांच में पाया है कि जिस तरीके से टिड्डियों के हमले हो रहे हैं उसमें बदलाव आया है। इसकी वजह भारत ही नहीं बल्कि उन इलाकों में हो रही बेमौसमी बारिश है जहां टिड्डियां पनपती हैं। इनमें लाल सागर के तट से अरब प्रायद्वीप, ईरान और राजस्थान शामिल हैं। यह कीट बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाता है और टिड्डियों के एक औसत झुंड में 80 लाख तक कीट हो सकते हैं। यह झुंड एक दिन में 2,500 लोगों या 10 हाथियों के बराबर खाना खा सकता है। पहले प्रजनन काल में 20 गुना बढ़ता है। दूसरे प्रजनन काल में यह 400 गुना और तीसरे प्रजनन काल में 16,000 गुना बढ़ता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर प्रजनन काल लंबा होगा तो इसकी संख्या में भारी इजाफा होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि टिड्डियों का झुंड हमें अकाल की याद दिलाता है।

इस साल टिड्डियों के झुंड बहुत बड़े थे और इस वजह से ज्यादा तबाही हुई। क्यों? इसके कई कारण हैं जिनकी पड़ताल की जरूरत है। पहली वजह यह थी कि इस बार पाकिस्तान के सिंध प्रांत और पश्चिमी राजस्थान में बेमौसम बारिश हुई थी। भारत का मरुस्थल टिड्डियों के प्रजनन के लिए मुफीद जगह नहीं है। इन कीटों को अपना परिवार बढ़ाने के लिए गीली और हरी जमीन की जरूरत होती है। लेकिन पिछले साल इस इलाके में समय से पहले बारिश हुई। यही वजह थी कि मई 2019 में ही वहां टिड्डियों के हमले की खबरें आने लगी थी। लेकिन इन्हें नजरंदाज किया गया। इसके बाद मॉनसून ज्यादा लंबा खिंच गया। अक्टूबर तक इसकी वापसी नहीं हुई थी। बारिश जारी रही और कीट पश्चिम एशिया और अफ्रीका की ओर पलायन करने के बजाय यहीं जमे रहे और प्रजनन करते रहे।

दूसरी वजह यह रही कि मई 2018 में चक्रवाती तूफान मेकुनू और फिर अक्टूबर 2018 में चक्रवाती तूफान लुबान के कारण अरब प्रायद्वीप में भारी बारिश हुई। इससे मरुस्थल में झीलें बन गईं जो कीटों के प्रजनन के लिए आदर्श स्थिति है।

टिड्डियों ने इन गरीब और युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई लेकिन बाहरी दुनिया को इसकी जानकारी नहीं मिली। फिर लाल सागर के तटीय इलाकों में पिछले साल जनवरी में भारी बारिश हुई। यह भी बेमौसम बारिश थी। वहां बरसात का मौसम नौ महीने तक खिंच गया और इस दौरान टिड्डियों ने अपनी तादाद में भारी इजाफा किया।

टिड्डियों के प्रकोप पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि लाल सागर के तटीय इलाकों में पर्याप्त फसल नहीं हो पाई। साथ ही समुद्री चक्रवाती तूफानों और हवा के प्रवाह में बदलाव के कारण टिड्डियां भारत पहुंच गईं। अमूमन टिड्डियां मॉनसूनी हवाओं के साथ भारत आती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2019 में टिड्डियां लाल सागर को पार करते हुए अफ्रीका और फारस की खाड़ी से होते हुए ईरान पहुंचीं। सर्दियों में टिड्डियों का दल ईरान में आराम करता है। वहां से उन्होंने भयंकर झुंडों के रूप में पाकिस्तान और भारत का रुख किया।

टिड्डियों के झुंड ने जब गुजरात और राजस्थान के बाद पाकिस्तान और ईरान की ओर लौटना शुरू किया तो तीसरी पीढ़ी के कीट पैदा हो चुके थे। इनका जन्म राजस्थान में मॉनसून की अवधि बढ़ने के कारण हुआ था। यही वजह है कि इस साल नुकसान अधिक हुआ है। किसान बुरी स्थिति में हैं। अब इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि इस क्षेत्र में बेमौसम बारिश या बार-बार समुद्री चक्रवाती तूफान आने की वजह जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है। इसलिए इस बात को समझना मुश्किल नहीं है कि परस्पर निर्भर और वैश्वीकृत दुनिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है। यह केवल लोगों या पूंजी के प्रवाह के बारे में नहीं है। यह केवल ग्रीनहाउस गैसों के बारे में नहीं हैं जो किसी सीमाओं में नहीं बंधी हैं। इसका संबंध जलवायु परिवर्तन के कारण कीटों के प्रकोप और कीटों के हमलों के वैश्वीकरण से है।

लेकिन हमारी असमान और सूचना-विभाजित दुनिया में जो बात इसे ज्यादा घातक बनाती है, वह यह है कि हम ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग के बारे में तो जानते हैं लेकिन अपने इलाके में हो रहे टिड्डियों के हमले से अनभिज्ञ हैं। हम यह संबंध नहीं बना रहे हैं। अफ्रीका से एशिया तक हम अपने लोगों का दर्द नहीं समझ सकते हैं जो पहले से ही जलवायु से जुड़े जोखिम वाले भविष्य में जी रहे हैं। इसलिए उन्हें जलवायु परिवर्तन के बारे में बताने या भाषण देने की बात भूल जाइए। इस समस्या से निपटने के लिए मिलकर काम कीजिए। इसकी समस्या हम हैं। वे हमसे पीड़ित हैं। यह ठीक नहीं है।

(लेखक सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवॉयरनमेंट से संबद्ध हैं)

कानाफूसी

पत्रकारों की मुश्किल

पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल एक मंत्री की मीडिया टीम और उनके मंत्रालय से संबद्ध पत्र सूचना कार्यालय की टीम के बीच तालमेल की कमी ने संबंधित बीट कवर करने वाले पत्रकारों के लिए भ्रम और देरी की स्थिति निर्मित कर दी है। यह इससे पहले वाले मंत्री की स्थिति से एकदम उलट है। उनकी व्यक्तिगत मीडिया टीम मंत्रालय के कदमों को लेकर अग्रिम जानकारी का प्रमुख जरिया थी। नए मंत्री की मीडिया टीम काम संभालने के कई महीने बाद भी अभी तक ठीक से सहज नहीं हो पाई है। इसका खमियाजा पत्रकारों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि मीडिया टीम उनसे बात करते हुए भी अतिरिक्त सतर्कता बरतती है। सवाल यह है कि कहीं यह मंत्रालय भी वित्त मंत्रालय की राह पर तो नहीं चल निकलेगा जिसने गत वर्ष जुलाई से ही पत्रकारों का प्रवेश प्रतिबंधित कर रखा है।

बेरोजगारी रजिस्टर!

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का मसला इन दिनों मीडिया पर छाया हुआ है। कांग्रेस ने इस सिलसिले में राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्टर (एनयूआर) शीर्षक से एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के हर जिले में बेरोजगार युवाओं के आंकड़े जुटाएंगे। बाद में इस आंकड़े को राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित किया जाएगा। इसका इस्तेमाल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने के लिए किया जाएगा। युवा कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने इस सिलसिले में अभियान शुरू भी कर दिया है। पार्टी ने इस संबंध में एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। बेरोजगार युवा उस पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीयन एनयूआर में करा सकते हैं।

आपका पक्ष

सीएए के लिए क्यों नहीं जाते अदालत

देश की संसद ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पारित किया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे गैर मुस्लिम लोगों को भारत में नागरिकता मिल सकेगी। इस कानून का अभी बीज ही बोया गया है। जब तक यह फल नहीं देने लगे तब तक इसका आकलन करना उचित नहीं है। वहीं नागरिकता संशोधन कानून जब तक पूरे देश में लागू नहीं हो जाता तथा सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले पर फैसला नहीं हो जाता तब तक इसका विरोध करना नासमझी ही होगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जितनी मुख्य भूमिका लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की होती है, उतनी ही लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए विपक्ष की भी जरूरत होती है। लेकिन वर्तमान में देश की राजनीति अवसरवाद की शिकार होती दिख रही है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को न तो संविधान की चिंता है और न ही न्यायपालिका पर भरोसा रह गया है। सीएए पर विपक्षी पार्टियां अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए धर्म विशेष के लोगों को गुमराह कर रही हैं। नागरिकता संशोधन कानून को संसद ने पारित कर दिया है जिसके बाद इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन संसद से पारित किसी कानून को लेकर अगर कोई उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे तो अदालत उसकी संवैधानिकता पर फैसला लेने के लिए तैयार हो सकता है। केरल सरकार ने सीएए को लेकर अदालत की शरण ली है। ऐसे लोग जो सीएए को राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि देश का सर्वोच्च न्यायालय न तो किसी सरकार की और न ही किसी धर्म विशेष के लोगों की हाथ की कठपुतली है। अत: हिंसा के साथ विरोध करने वालों को अदालत की शरण लेनी चाहिए जिससे विरोध के नाम पर हिंसा पर रोक लग सके।

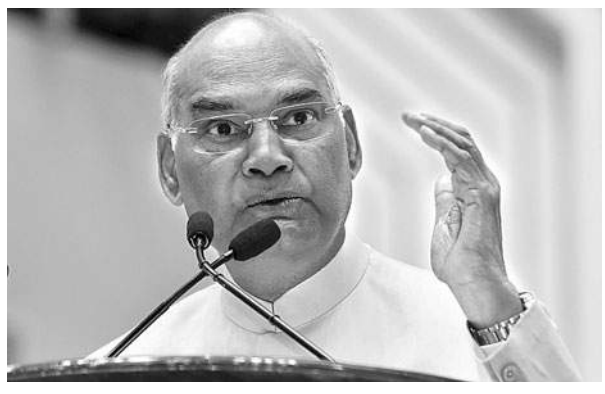

सीएए के विरोध में हिंसा के खिलाफ कई प्रबुद्ध लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सरकारी अस्पतालों की बदहाली दूर हो

सरकारी अस्पतालों में किसी मरीज को इलाज के लिए पहले ओपीडी से 15 रुपये की पर्ची बनानी पड़ती है जिसके बाद डॉक्टर मरीज की जांच करते हैं। निजी डॉक्टरों को दिखाने की फीस तकरीबन 400 रुपये हैं। सरकारी अस्पतालों में किसी भी बीमारी की दवा मुफ्त में मिल जाती है। सरकारी अस्पताल में फीस का कम होना तथा मुफ्त में दवा मिलना इनकी बदहाली का एक कारण हो सकता है। सरकारी अस्पतालों की बदहाली दूर करने के लिए केवल गरीबों का इलाज मुफ्त में करना चाहिए। इसके लिए गरीबों की परिभाषा तय करने की जरूरत है। एक निश्चित आय वर्ग को अर्थात गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का ही इलाज मुफ्त होना चाहिए। इसके अलावा अस्पतालों की देखभाल का जिम्मा शहर के नगर निगम तथा नगरपालिका को दे देनी चाहिए। बहरहाल सरकारी अस्पताल के कारण ही लाखों गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो पाता है तथा गंभीर रोग का भी इलाज होने से गरीब मरीजों की जान बच जाती है।

राकेश जैन, सतना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

मलेशिया से पाम तेल आयात में भारी गिरावट

मलेशिया से भारत का मासिक पाम तेल आयात जनवरी में गिरकर लगभग नौ साल के निचले स्तर पर आ सकता है क्योंकि कारोबारियों ने भारत सरकार के अनौपचारिक निर्देशों के बाद मलेशिया से इस उष्णकटिबंधीय तेल की खरीद बंद कर दी है। कारोबारियों और रिफाइनरों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी है। दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल आयातक भारत द्वारा आयात में कमी किए जाने से मलेशिया के दामों पर दबाव बन सकता है। इस महीने की शुरुआत में तीन साल के शीर्ष स्तर पर जाने के बाद वह दामों में करीब 10 प्रतिशत की कमी कर चुका है।

कश्मीर में भारत की कार्रवाई और नए नागरिकता कानून की मलेशिया के प्रधानमंत्री द्वारा आलोचना किए जाने के बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह में भारत सरकार ने पाम तेल आयातकों से मलेशिया के उत्पादों का बहिष्कार करने का अनुरोध किया था। कुछ कारोबारी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार द्वारा संचालित कंपनियां निविदा जारी करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए रिफाइंड पाम तेल की खरीद कर सकती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। कुआलालम्पुर स्थित एक कारोबारी ने कहा कि फरवरी की खेपों के लिए कोई भी कारोबारी मलेशिया का कच्चा पाम तेल (सीपीओ) या पामोलिन नहीं खरीद रहा है। सरकारी एजेंसियों से अब तक कोई खुली निविदा नहीं आई है।

कारोबारियों और रिफाइनरों का कहना है कि जनवरी में भारत मलेशिया से 70,000 टन से भी कम पाम तेल का आयात करने जा रहा है जो अप्रैल 2011 के बाद का सबसे कम स्तर है और जनवरी 2019 में किए गए 2,53,889 टन की तुलना में काफी कम है। फरवरी में आयात 10,000 टन से भी कम के मामूली स्तर पर रह सकता है क्योंकि लगभग सभी भारतीय खरीदार इंडोनेशिया का रुख कर चुके हैं। एक वैश्विक कंपनी के मुंबई स्थित कारोबारी ने कहा कि सरकार द्वारा मौखिक निर्देश दिए जाने के बाद कारोबारियों ने मलेशिया से खरीद रोक दी है। इस महीने की खेपें सरकार के निर्देशों से पहले किए गए अनुबंधों के जरिये हो रही हैं। *रॉयटर्स*

रबी सत्र में अधिक उत्पादन के आसार

पर्याप्त नमी के कारण इस वर्ष रबी में फसलों का रकबा रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा

सुशील मिश्र
मुंबई, 27 जनवरी

चालू रबी सत्र के दौरान पर्याप्त नमी से इस वर्ष देश में फसलों के रकबे ने कीर्तिमान स्थापित किया है। गेहूं और चने के रकबे में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इससे रबी सत्र में फसलों का उत्पादन सरकारी अनुमान से भी बेहतर होने की संभावना है। फसल उत्पादन का अनुमान लगाने वाली निजी प्रबंधन कंपनी नैशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एनसीएमएल) ने रबी सत्र के अपने पहले उत्पादन अनुमान में उत्पादन पिछले साल और सरकारी लक्ष्य से भी अधिक रहने की संभावना जताई है। इस अनुमान में चने का उत्पादन कम बताया गया है, जबकि सरकार ने चने का उत्पादन लक्ष्य अधिक रखा है।

कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 654.13 हेक्टेयर में बुआई हुई है, जबकि पिछले साल 597.52 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस साल 56.61 लाख हेक्टेयर रकबा बढ़ा है। अधिक बुआई और खेतों में पर्याप्त नमी की वजह से इस साल बेहतर उत्पादन के आसार हैं। सरकार ने चालू रबी सत्र में फसल उत्पादन का लक्ष्य 1,534.61 लाख टन रखा है। एनसीएमएल ने रबी सत्र के अपने पहले उत्पादन अनुमान में उत्पादन 1,633.91 लाख टन रहने का अनुमान जताया है, जो सरकारी लक्ष्य और पिछले साल के उत्पादन से अधिक है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक रबी सत्र 2018-19 में कुल उत्पादन (चौथा फसल उत्पादन अनुमान) 1,542.19 लाख टन था। एनसीएमएल के अनुमान के मुताबिक चालू रबी सत्र में कुल उत्पादन पिछले रबी सत्र की तुलना में करीब छह फीसदी और सरकारी अनुमान से 6.5 फीसदी अधिक रहेगा।

रबी फसल उत्पादन (लाख टन में)

फसल	2018-19 चौथा अ. अनु.	2019-20 उत्पादन अनु.	2019-20 लक्ष्य	अंतर प्रतिशत
गेहूं	1021.90	1090.30	1005	8.5
चावल	142.90	149.70	140	6.9
ज्वार	20.20	31.20	21	48.6
मक्का	81.80	89.20	76	17.4
जौ	17.50	20.60	21	-1.9
अन्य	0	1.10	0	–
कुल	1284.30	1382.02	1270	8.8
चना	101.30	95.82	116	-17.4
उड़द	7.00	7.18	8	-10.3
मूंग	5.10	4.62	7	-34.0
मसूर	15.60	15.15	–	–
अन्य दलहन	19.00	22.07	31	-28.8
कुल	148.00	144.83	162	-10.6

स्रोत- एनसीएमएल और कृषि मंत्रालय, संकलन- बीएस रिसर्च

नवंबर से अप्रैल तक चलने वाले रबी सत्र में वर्ष के करीब आधे खाद्यान्न का उत्पादन होता है। एनसीएमएल के मुताबिक इस बार मॉनसून में सामान्य से करीब 10 फीसदी अधिक बारिश हुई जिसके कारण खेतों में नमी बनी रही और इस वजह से फसल बेहतर है। रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल गेहूं का उत्पादन पिछले सत्र से 6.27 फीसदी बढ़कर 1,090.3 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 1,021.90 लाख टन उत्पादन हुआ था। गेहूं उत्पादन अधिक होने की एक प्रमुख वजह रकबा बढ़ना है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अब तक 334.35 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हो चुकी है जो पिछले साल से 35.28 लाख हेक्टेयर अधिक है। बुआई देर से शुरू होने से सरकार ने चालू सत्र में 1,005 लाख टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा था।

एनसीएमएल ने रबी की दूसरी प्रमुख फसल चने का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 5.72 फीसदी कम रहने का अनुमान लगाया है। चालू सत्र में 95.82 लाख टन चना उत्पादन का अनुमान है, जबकि पिछले सत्र में 101.30 लाख टन उत्पादन हुआ था। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में 106.40 लाख हेक्टेयर में चने की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल 95.89 लाख हेक्टेयर था। रिकॉर्ड बुआई के कारण कृषि मंत्रालय की तरफ से 116 लाख टन चना उत्पादन लक्ष्य रखा गया था, जो एनसीएमएल के पहले फसल अनुमान में पूरा होता नहीं दिख रहा है। एजेंसी के अनुमान के मुताबिक रबी सत्र में दलहन फसलों का उत्पादन 144.83 लाख टन होने की संभावना है, जबकि पिछले सत्र में दलहन फसलों का उत्पादन 148 लाख टन था।

एनसीएमएल के प्रबंध निदेशक सिराज चौधरी के मुताबिक मॉनसून में भरपूर बारिश से रबी सत्र में फसल उत्पादन की संभावना को बढ़ा दिया है। इस बार मक्का, ज्वार और गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है, लेकिन तिलहन और दलहन फसलों का उत्पादन पिछले रबी सत्र की तुलना में कम होने की आशंका है। चालू सीजन में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा सहित सभी मोटे अनाजों का उत्पादन पिछले साल के 1,284.3 लाख टन की तुलना में सात फीसदी बढ़कर 1,382.02 लाख टन रहने का अनुमान है। दलहन का उत्पादन पिछले साल से 2.19 फीसदी कम होकर 144.83 लाख टन और तिलहन 2.69 फीसदी फिसलकर 106.91 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है।

सरकारी अनुमान में बढ़ा प्याज उत्पादन

बीएस संवाददाता/ भाषा
नई दिल्ली, 27 जनवरी

पिछले साल खरीफ सत्र में प्याज को नुकसान के दावे के बीच अब चालू फसल वर्ष 2019-20 में प्याज उत्पादन सात प्रतिशत बढ़कर 2.44 करोड़ टन रहने का सरकार का अनुमान है। पिछले कुछ महीनों के दौरान प्याज के ऊंचे दाम से त्रस्त ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। चालू फसल वर्ष में बागवानी फसलों के कुल उत्पादन में मामूली इजाफा हो सकता है।

कृषि मंत्रालय ने पहला अनुमान जारी करते हुए कहा कि फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) में प्याज फसल का रकबा बढ़कर 12.93 लाख हेक्टेयर रहा। यह पिछले फसल वर्ष के 12.20 लाख हेक्टेयर से कुछ अधिक है। इसके परिणामस्वरूप प्याज का उत्पादन इस साल बढ़कर 2.44 करोड़ टन होने का अनुमान है जो 2018-19 में 2.28 करोड़ टन था। प्याज का उत्पादन खरीफ और रबी दोनों मौसम में होता है।

मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि देर से और अत्यधिक बारिश के कारण खरीफ सीजन में 22 प्रतिशत प्याज फसल को नुकसान हुआ। फसल खराब होने से प्याज की कीमत पिछले कुछ महीनों के दौरान 160 रुपये किलो तक पहुंच गई थी। हालांकि, अभी इसमें कुछ कमी आई है और यह फिलहाल 60 रुपये किलो के आसपास है। आलू का उत्पादन इस साल मामूली बढ़कर 5.194 करोड़ टन रहने का अनुमान है जो पिछले साल 5.019 करोड़ टन था। वहीं टमाटर का उत्पादन भी कुछ बढ़कर 1.932 करोड़ टन रहने की संभावना है जो पिछले साल 1.9 करोड़ टन रहा था।

मंत्रालय के अनुसार बीन, परवल और कद्दू के उत्पादन में मामूली गिरावट का अनुमान है। हालांकि, सब्जियों का कुल उत्पादन फसल वर्ष 2019-20 में कुछ बढ़कर 18.8 करोड़ टन रह सकता है जो पिछले साल में 18.3 करोड़ टन था। प्रमुख फलों में सेब उत्पादन इस साल बढ़कर 27.3 लाख टन रहने का अनुमान है जो पिछले साल 23.1 लाख टन था। हालांकि, आम, केला, अंगूर और अनार के उत्पादन में गिरावट आने का अनुमान है। आम का उत्पादन 2019-20 में मामूली रूप से घटकर 2.13 करोड़ टन रह सकता है जो एक साल पहले 2.14 करोड़ टन था। वहीं केला का उत्पादन 3.05 करोड़ टन से कम होकर 2.964 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Jan 27	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,775.5	3.8	2,057.7	7.3
Copper	5,968.0	1.7	6,397.0	4.7
Nickel	12,990.0	-23.1	13,717.8	-20.9
Lead	1,960.0	-12.7	2,169.7	1.9
Tin	16,900.0	1.8	17,637.2	0.0
Zinc	2,354.5	-7.4	2,561.6	-4.9
Gold ($/ounce)	1,582.7*	5.2	1,769.8	4.6
Silver ($/ounce)	18.3*	1.2	20.6	0.5
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	58.6*	-4.7	62.5	1.5
Natural Gas ($/mmBtu)	1.9*	-15.7	1.9	-21.7
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	200.9	13.9	290.5	-4.3
Maize	187.7*	3.1	271.4	-3.3
Sugar	393.1*	16.6	486.9	-1.3
Palm oil	765.0	33.6	1,189.8	31.1
Rubber	1,426.2*	5.4	1,903.7	9.3
Coffee Robusta	1,314.0*	7.7	1,770.7	-7.4
Cotton	1,513.5	5.8	1,569.4	-2.5

* As on Jan 27, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.4& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	190.7	36611
Oil and Oilseeds	340.2	82378
Spices	1.2	9
Metal(Jan 24)		
Metal- non ferrous	6041.2	52859
Metal- precious	14254.5	394
Oil and gas(Jan 24)		
Gas	2629.8	57131
Oil	14353.9	2430

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	249.0	114175
Grains	178.7	98270
Oil and Oilseeds	1096.2	469355
Others	147.6	66975
Pulses	74.2	32015
Spices	51.1	22714

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Cardamom (Feb 14)	3915.0	1.7
Aluminium (May 29)	143.3	1.4
Silver Mini (Feb 28)	46959.0	1.2
Silver (Mar 05)	46935.0	1.2
Silver Micro (Feb 28)	46954.0	1.2
Losers (* % Change)		
Crude Palm Oil (Jan 31)	763.4	-3.0
Natural Gas (Jan 28)	134.4	-2.9
Nickel (Jan 31)	976.2	-2.7
Cotton (Jan 31)	19060.0	-1.8
Copper (Jan 31)	438.7	-1.6
Crude Oil (Feb 19)	3873.0	-1.5
Mentha Oil (Jan 31)	1211.0	-1.4

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Losers (* % Change)		
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	845.2	-3.3
Soyabean Indore (Feb 20)	4006.0	-3.2
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6210.0	-2.4
GuarGum 5T-Jodhpur (Feb 20)	7174.0	-2.3
Coriander-Kota (Apr 20)	6559.0	-2.2
Guar Seed 10 (Feb 20)	4024.0	-2.0
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	4002.0	-1.9
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	1900.0	-1.7
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1083.0	-1.3
Chana-Bikaner (Mar 20)	4046.0	-1.3
Mustard Seed Rape Oil (Feb 20)	4162.0	-1.3
Jeera Unjha (Mar 20)	14485.0	-1.1
Barley Jaipur (Apr 20)	1708.5	-0.4

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1070.0	4.2
Nickel Mumbai (Jan 31)	976.2	1.8
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	3915.0	1.0
Zinc Mumbai (May 29)	183.8	0.9
Copper Mum (Jan 31)	438.7	0.7
Cotton-Rajkot (Jan 31)	19060.0	0.3
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1211.0	-11.4
Lead Min Mumbai (Jan 31)	149.5	-5.2
Alumini-Mumbai (Jan 31)	139.7	-3.7
Gold Petal-Mumbai (Jan 31)	3962.0	-2.8
Lead Mum (May 29)	154.3	-2.1
Zinc Mini Mumbai (Jan 31)	179.0	-1.8

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6210.0	2.5
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	766.9	2.1
Bajra-Jaipur (Feb 20)	1906.0	1.9
29 mm Cotton-Rajkot (Feb 20)	19270.0	1.1
Paddy-Basmati-Karnal (Feb 20)	3214.0	0.4
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1708.5	-21.1
Jeera Unjha (Mar 20)	14485.0	-6.1
Soy Bean Indore (Feb 20)	4006.0	-3.4
Coriander-Kota (Apr 20)	6559.0	-2.3
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	7174.0	-1.7
Bajra-Delhi (Feb 20)	1906.0	-1.2

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	109.....(109)
Aluminium ingots /kg	147.....(147)
Brass sheet cutting /kg	330.....(332)
Brass utensil scraps/kg	310.....(311)
Copper heavy scrap /kg	422.....(429)
Copper utensil scraps/kg	397.....(398)
Copper wire bar /kg	457.....(461)
Lead ingots /kg	155.....(156)
Nickel Cathodes /kg	980.....(1010)
Tin slabs /kg	1260.....(1280)
Zinc slabs /kg	183.....(186)
Source:Bombay Metal Exchange	
Cotton	**Mumbai**
Bengal Deshi /Qtl	10236.....(10292)
DCH - 32 /Qtl	11557.....(11389)
Jaydhar /Qtl	9758.....(9842)
Shankar- 6 /Qtl	11079.....(11164)
Source:Cotton Association of India	
Oil	**Mumbai**
Castor FSG /10kg	866.....(872)
Castor Comm /10kg	856.....(862)
Ricebran oil/10kg	820.....(820)
Groundnut oil /10kg	1150.....(1140)
Linseed oil /10kg	965.....(965)
Karanji /10kg	800.....(800)
Palm oil /10kg	840.....(855)
Sunflower exp ref /10kg	885.....(895)
Sunflower oil exp /10kg	860.....(860)
Soyabean ref / 10kg	880.....(885)
Source:Bombay Commodity Exchange	

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3372-3585 .....(3382-3585)
Source:Bombay Sugar Merchants Association	

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	52.41.....(54.19)
Brent Crude (UK)	58.04 .....(60.01)
Brent Crude (WTI)	54.12.....(54.12)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.94 .....(1.89)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	311.01 .....(312.2)
Naptha spot /Rs/MT	45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950.....(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com	

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	40651.....(39996)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40814.....(40157)
Silver.999/ kg	47395.....(46145)
Source:India Bullion & Jewellers Association	

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	19189.55	19066.25
Alumini-Mumbai (M)	1 K	145.30	145.05
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1925.00	1930.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1897.70	1870.65
Barley Jaipur (N)	1 Q	2172.80	2164.40
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3892.00	3883.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4165.40	4132.15
Castor Seed-Kadi (N)	X	4140.00	4140.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4201.65	4150.00
Chana Delhi (N)	1 Q	4412.50	4350.00
Chana-Akola (N)	X	4160.00	4075.00
Coriander-Gondal (N)	X	6483.00	6439.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6717.50	6600.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	6735.05	6711.30
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2011.20	1971.75
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2007.75	2000.00
Cotton-Kadi (N)	1 B	19170.40	19006.10
CPO-Kandla (M)	10 K	788.00	771.80
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	766.00	751.35
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	780.00	760.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	906.95	909.15
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1551.70	1554.95
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3453.25	3459.10
Gold Ahm (M)	10 G	40002.00	40638.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32130.00	32641.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4016.00	4078.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7375.00	7294.80
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4033.25	3996.65
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3983.00	4013.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1094.45	1103.95
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	105.20	103.55
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16150.00	16150.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	15500.00	15420.00
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	890.25	870.65
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1042.15	1033.40
Kapas-Rajkot (N)	X	1050.10	1035.20
Lead Mum (M)	1 K	154.90	157.65
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1956.90	1942.50
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2263.45	2280.55
Maize-Erode (N)	X	1960.65	1950.00
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	2263.45	2280.55
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2140.00	2125.00
Maize-Sangli (N)	X	1930.90	1940.00
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4850.00	4750.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7711.10	7800.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4411.25	4372.65
Nickel Mumbai (M)	1 K	1005.00	958.70
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3200.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3252.00	3260.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	336.40	336.80
Pepper-Kochi (N)	1 Q	33875.00	33816.65
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	865.00	860.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	773.00	765.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1916.40	1900.00
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5400.00	5299.05
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	860.90	850.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	897.50	880.00
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	891.35	882.95
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	905.00	887.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13700.00	13600.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13700.00	13667.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46116.00	47320.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4242.00	4147.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4166.25	4076.25
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4292.50	4166.25
Soy Bean-Akola (N)	X	4221.00	4100.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33750.00	33025.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	898.90	885.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	32200.00	32330.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	32210.00	32500.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	29280.00	29480.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3265.00	3255.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3370.55	3419.05
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3300.00	3300.00
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3490.50	3476.20
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3307.75	3290.50
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3151.00	3146.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6082.25	6055.70
Wheat Delhi (N)	1 Q	2200.00	2206.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2200.00	2166.65
Wheat New Indore (N)	1 Q	2205.00	2200.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2142.50	2105.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2225.00	2200.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5500.00	5600.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5800.00	5837.50
Zinc Mumbai (M)	1 K	184.75	182.25

* as on Jan 24, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (सोमवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19300, 19310, 18950, 19060	6118	679	7037
Feb 28	19600, 19600, 19220, 19330	8835	1054	25268
Mar 31	19840, 19840, 19540, 19590	1671	259	3461
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	1926, 1950, 1868, 1900	76010	5074	65640
Mar 20	1950, 1976, 1900, 1926	27020	2265	30580
Apr 20	1976, 2004, 1930, 1955	4680	415	12300
May 20	1988, 2026, 1959, 1996	500	48	1890
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1090.5, 1091, 1079, 1082	344	66	820
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1090, 1094.5, 1078, 1083	1918	1050	3765
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1715.5, 1715.5, 1701, 1708.5	600	18	2000
May 20	1715.5, 1715.5, 1701.5, 1710	350	14	1670
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	4090, 4090, 4006, 4024	32895	3713	79445
Mar 20	4110, 4124, 4050, 4068	10715	1246	14905
Apr 20	4130, 4140, 4106, 4110	55	11	130
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	4072, 4080, 3986, 4002	7355	816	20740
Mar 20	4084, 4084, 3988, 4000	3430	459	10830
Apr 20	4074, 4086, 4000, 4014	440	59	3440
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	777, 781.4, 758.6, 763.4	9710	719	21410
Feb 28	763, 764.5, 738, 745.4	25440	1961	46950
Mar 31	754.7, 761.4, 734.5, 740.4	5670	451	13420
Apr 30	749.8, 749.8, 734.6, 742.7	80	7	330
Mentha Oil MCX(1 K)				
Jan 31	1241.3, 1241.3, 1202, 1211	53.28	136	54.72
Feb 28	1246.6, 1251, 1220.7, 1222.9	199.8	453	209.52
Mar 31	1225.1, 1225.1, 1225, 1225.1	0.72	2	0.36
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4207, 4210, 4145, 4162	18080	1438	12320
Apr 20	4260, 4260, 4145, 4179	16930	1344	10440
May 20	4259, 4259, 4159, 4179	2630	223	2460
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	863, 863, 837.6, 845.2	33045	3779	52410
Mar 20	853, 853, 829.8, 834.2	15750	1782	33695
Apr 20	847.6, 848.8, 830.4, 831	860	106	4015
May 20	844.4, 844.4, 830, 832	30	6	100
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4110, 4120, 3974, 4006	63205	6109	134460
Mar 20	4112, 4112, 3968, 3990	35575	4508	121030
Apr 20	4104, 4110, 3978, 3988	12480	1800	51745
May 20	4114, 4126, 3992, 3998	5850	567	11565
Jun 19	4050, 4086, 4016, 4030	185	35	100
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	7320, 7320, 7138, 7174	12265	1630	42985
Mar 20	7380, 7380, 7225, 7260	7860	833	23820
Apr 20	7450, 7450, 7417, 7440	200	29	170
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	4071, 4071, 4037, 4046	13870	996	21720
Apr 20	4064, 4064, 4019, 4027	4030	295	8110
May 20	4105, 4115, 4050, 4063	450	42	2130
Jun 19	4132, 4132, 4132, 4132	10	1	10
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Feb 14	3900, 3925, 3900, 3915	0.3	3	5.6
Mar 13	3768.5, 3950, 3768.5, 3911.8	2.8	27	3.2
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	6690, 6720, 6528, 6559	3090	280	9260
May 20	6660, 6660, 6570, 6570	30	3	390
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	14655, 14775, 14400, 14485	957	302	2118
Apr 20	14475, 14480, 14215, 14250	498	155	1251
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6390, 6390, 6192, 6210	1090	204	5035
Apr 20	6226, 6226, 6084, 6110	400

आम लोगों को राहत देने वाला हो आम बजट

दीपक शर्मा

मंदी से उबारने वाला हो बजट

छह साल के निचले स्तर पर पहुंची भारत की आर्थिक वृद्धि दर को रफ्तार देने के लिए ढांचागत सुधारों की उम्मीद में बजट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आर्थिक सुस्ती के कारण यह बजट अहम माना जा रहा है। अच्छे बजट से ही हमें पता चल पाता है कि हमें अपना पैसा कहां सुरक्षित रखना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई की समस्या से लोग परेशान हैं। हर क्षेत्र में मंदी दिखाई दे रही है। ऐसे हालात में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद है कि वह बजट में रोजगार सृजन, मध्यम वर्ग को सहूलियत देने के साथ-साथ उद्योगों को भी गतिशील बनाने का प्रयत्न करेंगी।

रुबी सिंह
असुरन चौक, उत्तर प्रदेश

ग्रामीण क्षेत्रों का भी रखें ध्यान

केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की योजना बजट के माध्यम से प्रस्तुत करनी चाहिए। बजट रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला हो। इस बजट में निम्न मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, छोटे उद्योग और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की जरूरत है। बजट में कर की दर में कटौती और बदलाव किए जाएं। बजट में सरकार रेलवे की दशा सुधारने के लिए रणनीतिक कदम बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रस्तुत करे। बजट में ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उपाय हों।

कुमारी कबिता
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

कराधान में बदलाव जरूरी

कराधान बजट का मुख्य हिस्सा है। पिछले साल कॉरपोरेट कर में कटौती के बाद से ही लोग आयकर में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। बजट में इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आयकर में कमी से करदाता की क्रयशक्ति बढ़ेगी जिससे खपत बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इस समय देश की अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में है। इसलिए बजट का ध्यान मंदी से उबरने पर होना चाहिए। सरकार ने अगले 5 साल में अर्थव्यवस्था को 5 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। बजट के प्रस्ताव इस लक्ष्य की प्रगति में सहायक होने चाहिए। राजस्व संग्रह की दृष्टि से भले ही जीएसटी से लक्ष्य की प्राप्ति न हुई हो, लेकिन यह महत्त्वपूर्ण कर सुधार है। इसमें अभी काफी सुधार की गुंजाइश है। इन दिनों सुस्ती की चपेट में चल रहे रियल एस्टेट उद्योग को भी बजट में प्रोत्साहन की दरकार होगी।

डॉ. एम एस सिद्दीकी
फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

युवाओं व कृषि बुनियादी ढांचे पर ध्यान

बजट में किसानों और युवाओं के कल्याण व उत्थान पर ध्यान होना चाहिए। किसानों की आय 2020 तक दोगुनी करने के सरकारी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कृषि उपकरणों की बिक्री पर कर घटाने व खाद सब्सिडी बढ़ाने जैसे प्रावधानों के साथ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी जरूरी है। कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण हाट जैसी योजनाओं के लिए विशेष कोष, ई-नाम से मंडियों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त बजट चाहिए। बेरोजगारी में कमी लाने के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे। नए उच्च शिक्षण संस्थानों व कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना पर भी ध्यान देना चाहिए। वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य हासिल करने के लिए आवास ऋण में राहत के प्रावधान होने चाहिए।

ऋषभ देव पांडेय
जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़

जिससे देश में खुशहाली बढ़े

इस समय देश के करोड़ों लोग आम बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बजट में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार का विशेष ध्यान रहे, ऐसी उम्मीद है। इस बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, रोजगार बढ़ाने, आयकर की मौजूदा दरों में कुछ रियायत और कृषि क्षेत्र में किसान हितैषी योजनाओं की आस है। ऐसी उम्मीद है कि सरकार इन समस्याओं पर विशेष ध्यान रखकर ही बजट पेश करेगी। बजट में बैंकिंग क्षेत्र और रियल एस्टेट क्षेत्र में विशेष ध्यान की भी उम्मीद है।

संजय डागा
इंदौर, मध्य प्रदेश

कृषि का विकास, रोजगार सृजन हो

आम बजट से किसानों और युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ने की काफी उम्मीदें हैं। कृषि विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं के लिए बजट बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कोष बढ़ाना होगा। कृषि के संबंधित क्षेत्रों के विकास के जरिये रोजगार के अवसर सृजन करने की दिशा में ठोस रणनीति लानी होगी। पशुपालन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं में उपयोगी प्रावधान जोड़ने होंगे। मत्स्यपालन को प्रोत्साहित करने के लिए मत्स्य संपदा योजना को अधिक राशि दी जाए। विनिर्माण, बैंकिंग, कॉरपोरेट, ई-कॉमर्स के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने होंगे ताकि रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित हो सके। युवाओं के कौशल विकास के लिए नए व अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए मजबूत कार्ययोजना लानी चाहिए। नई ट्रेन चलाने के स्थान पर पुरानी पड़ चुकी पटरियों व डिब्बे को बदलने के साथ जरूरी मार्गों पर दोहरीकरण पर ध्यान हो।

डॉ नरेंद्रनाथ गुरिया
जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़

सभी वर्गों के हितों का ध्यान रहे

बजट से सभी वर्गों को अपनी समस्याओं को लेकर राहत की आस रहती है। आयकरदाता कर छूट की सीमा में वृद्धि को लेकर बैचेन रहते हैं। बजट में महंगाई से त्रस्त लोगों को निजात दिलाने के प्रावधान होने चाहिए। देश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सभी वर्गों के हितों का ध्यान सरकारी कोष पर भार बढ़ा सकता है। इस बार बजट में नौकरियां बढ़ाने, किसानों के हितों, रियल एस्टेट क्षेत्र को सुविधाएं देने, कर में राहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण जैसे मुद्दों को समाहित करने की जरूरत है। जिस प्रकार गत वर्ष स्वास्थ्य सेवाओं में संसाधनों की कमी व लापरवाही सुर्खियों में रही है, उसे दूर करने के लिए बजट में पर्याप्त धन आवंटित करने की जरूरत है।

प्रदीप माथुर
अलवर, राजस्थान

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की उम्मीद

आर्थिक विकास की दर पिछले 5 वर्षों के निम्नतम स्तर पर पहुंचने के बीच पेश होने जा रहे बजट में पूरी संभावना है कि मोदी सरकार बैंकिंग क्षेत्र के लिए कई सुधारवादी नीतियां लेकर आएगी। सरकार बजट में चुनिंदा सरकारी बैंकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती हैं। खुदरा क्षेत्र चाहता है कि सरकार को खपत बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि ग्राहकों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम हो। इसके लिए मुख्य उत्पादों से जीएसटी दर घटाने की जरूरत है। आयकर की छूट की सीमा बढ़ानी चाहिए। नौकरियों का सृजन होना चाहिए। किसानों की चाहत कम ब्याज दरों पर कृषि कर्ज की है। व्यापारी वर्ग को बजट में कॉरपोरेट कर में कमी की उम्मीद है।

सुधीर कुमार सोमानी
देवास, मध्य प्रदेश

लोकलुभावन हो सकता है बजट

देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव आम बजट के बाद होंगे। इस कारण आम बजट जनता की कसौटी पर खरा उतरने वाला हो सकता है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि सभी श्रेणी के करदाताओं को वर्तमान में मिल रही सभी प्रकार की रियायतें यथावत रहेंगी। उम्मीद है कि सरकार आयकर की मौजूदा दरों और श्रेणी में बदलाव करके समिति की सिफारिशों को मान लेगी। समिति ने 5 फीसदी कर के स्लैब में बदलाव नहीं करने की सिफारिश की है। समिति ने 5 से 10 लाख तक की आय पर 10 फीसदी, 10 से 20 लाख पर 20 फीसदी, 20 लाख से 2 करोड़ आय पर 30 फीसदी और 2 करोड़ रुपये से अधिक आय पर 35 फीसदी कर की सिफारिश की है। समिति ने 2 करोड़ और 5 करोड़ रुपये से अधिक आय पर लगने वाले अधिभार को समाप्त करने की सिफारिश भी की है।

अनिल कोथुलकर
इंदौर, मध्य प्रदेश

बचा जाए लोकलुभावन बजट से

देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक उठापटक को देखते हुए वित्त मंत्री को ही लोकहितकारी बजट बनाना होगा। चुनाव नहीं हैं और सरकार पर लोकलुभावन बजट पेश करने का दबाव नहीं है, इसलिए दूरदर्शिता के साथ ही बजट का खाका खींचा जाना चाहिए। हालांकि आयकर पर सबसे ज्यादा कयास लग रहे हैं मगर इस बार उसमें रियायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि दरें पहले ही कम हैं। रेलवे का निजीकरण और एयर इंडिया का विनिवेश भी अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी हो सकता है। पिछले वित्त वर्ष में आशानुरूप प्रदर्शन में नाकाम रहे क्षेत्रों को आकर्षक बनाने का जिम्मा भी बजट का ही है। दूरसंचार, उड्डयन, रियल एस्टेट, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तकनीकी के लिए विस्तृत कार्ययोजना बने।

डॉ आंजनेय गुप्ता
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

लोगों की उम्मीदों का बजट

पिछले एक वर्ष से अर्थव्यवस्था में निराशा का माहौल है, जिसे उबारने के उपाय बजट में करने होंगे। इस बजट में अमीरों, मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय, गरीबों, शोषित व किसानों के साथ ही उद्योगों, शिक्षा, रक्षा, रेल जैसे अनेक विषयों पर व्यापक मंथन कर सभी को प्रमुखता से देखने की जरूरत है। आर्थिक सुस्ती के कारणों को पहचान करके उन्हें लक्षित करके सुस्ती को दूर करने के उपाय बजट में होने चाहिए। बजट में मांग बढ़ाने के उपाय हों। इसके लिए कर दरों में छूट दी जाए। बजट में कृषि और बेरोजगारी की समस्या पर जोर देने की जरूरत है। बजट में लोगों को सहूलियत देते हुए विदेशी निवेशकों का भी ध्यान रखा जाए।

अंकित त्रिपाठी
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

लचीला होना चाहिए आम बजट

बजट में करदाताओं पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए और रक्षा बजट के लिए कहीं से भी कटौती नहीं की जानी चाहिए। बजट में किसानों के लिए नई तकनीक को प्रोत्साहन का प्रावधान होना चाहिए जो उन्हें पसलों की कटाई, बुआई, रोपाई, मड़ाई आदि में मदद कर सके। कृषि में उपयोग होने वाली खाद, यूरिया एवं बीजों पर अधिकाधिक सब्सिडी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि अन्नदाताओं की वार्षिक आय में बढ़ोतरी हो सके और उनका जीवन स्तर भी सुधर सके। स्वास्थ्य बजट में आयुष्मान भारत योजना की सुचारु रूप से सेवाएं प्रदान कराई जानी चाहिए और जटिल रोगों के इलाज के लिए अगर किसी को विदेश भी जाना पड़े तो उसका प्रावधान हो। अंततः बजट लचीला होना चाहिए ताकि गर्त में जा चुकी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाया जा सके।

डॉ रसिकेश नवजात
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

कर की दरों में एकरूपता हो

इस बार का बजट निश्चित रूप से वित्त मंत्री के लिए चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही देश में अशांति का माहौल है। अगर अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है तो ढांचागत क्षेत्र, रियल एस्टेट, बैंकिंग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र तथा एफएमसीजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना होगा। नोटबंदी के इतने वर्ष बाद भी व्यवसायी अब तक भयभीत हैं। लिहाजा बजट में नोटबंदी की मार झेल चुके व्यापारियों को राहत देनी चाहिए। कर की दरों को भी एकरूप और सम्यक किए जाने की जरूरत है। आयकर और जीएसटी की जगह कोई ऐसी कर योजना की जरूरत है जिसमें औपचारिकताएं कम और लोगों को सहूलियतें ज्यादा हों। राजस्व में वृद्धि करने के लिए सरकार को योजनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।

डॉ राम हर्ष गुप्ता
मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

रोजगार बढ़ाने वाला हो बजट

बजट से सभी वर्गों को उम्मीद लगी रहती है। बजट देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने वाला होना चाहिए। कारपोरेट कर में कटौती का लाभ उन कंपनियों को हुआ जो पहले से ही मुनाफा कमा रही हैं। नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी दर कम करने की जरूरत है। इससे मांग में वृद्धि होगी। आवास ऋण पर अनुदान का दायरा विस्तृत होना चाहिए। व्यक्तिगत आयकर दर किसी भी हालत में कॉरपोरेट कर की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के साधन जैसे मेडिक्लेम, जीवन बीमा आदि से जीएसटी हटना चाहिए। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर हो सकते हैं। अगर सरकार इन क्षेत्रों में समुचित ध्यान दे।

अजीत सिंह चौधरी
इंदौर, मध्य प्रदेश

बकौल विश्लेषक

ढांचागत खर्च में बढ़ोतरी से मिलेगी अर्थव्यवस्था को गति

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3 प्रतिशत तय किया गया था। हालांकि इस बात की काफी संभावना है कि आगामी बजट में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय घाटे के 3 प्रतिशत के लक्ष्य को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, केंद्र सरकार कर में कटौती के बजाए अधिक खर्च पर ध्यान देगी। नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के लिए गठित टास्क फोर्स की हालिया रिपोर्ट में इस मद के लिए वर्ष 2020-21 में केंद्र, राज्य तथा निजी क्षेत्र द्वारा कुल 19.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें केंद्र सरकार पूंजीगत खर्च के तौर पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 4.6 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। हालांकि इस मद हेतु वर्ष 2020-21 के लिए केवल 1.9 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रावधान एनआईपी रिपोर्ट में बताया गया था। इसलिए फिलहाल शेष 2.7 लाख करोड़ रुपये पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आगामी बजट में केंद्र सरकार सड़क, किफायती आवास, रेलवे, ऊर्जा आदि पर पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी कर सकती है। साथ ही, मनरेगा के लिए आवंटित राशि बढ़ाने से ग्रामीण उपभोग तथा मांग में तेजी आएगी। यह देखते हुए कि पीएम-किसान योजना में शामिल लाभार्थियों की संख्या अभी तक कम बनी हुई है, केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी के लिए आवंटित राशि को बढ़ा सकती है। इसके अलावा, रोजगार सृजन के उद्देश्य से ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। कर सुधार के क्षेत्र में सरकार ने पहले ही सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट कर की दरों में कटौती की घोषणा कर दी थी। इस बजट में आयकर तथा दूसरे प्रत्यक्ष करों में अधिक बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2020-21 का बजट एनआईपी में बताए गए क्षेत्रं समेत ढांचागत खर्च के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को गति देने पर केंद्रित रहेगा।

बातचीत : वीरेश्वर तोमर

अदिति नायर
मुख्य अर्थशास्त्री, इक्रा

सरल हो कंपनियों के लिए कर ढांचा

वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिहाज से कारोबारियों के लिए जरूरी कर सुधार किए जाने चाहिए। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में कई सुधार किए हैं लेकिन अभी भी काफी बदलावों की आवश्यकता है। वर्तमान व्यवस्था के तहत अगर किसी व्यक्ति ने रिटर्न के अनुसार देय राशि का भुगतान नहीं किया है तो वह रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। हालांकि अगर व्यक्ति रिटर्न के अनुसार जरूरी राशि का भुगतान करने में देरी करता है तो उससे ब्याज वसूला जा सकता है। फिलहाल पेट्रोलियम, शराब, बिजली, प्राकृतिक गैस एवं विमान टरबाइन ईंधन आदि को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है जिससे संबंधति क्षेत्र में कारोबार करने वाली कंपनियों को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सेवाओं के संबंध में 'क्रॉस चार्ज' को लेकर भी फिलहाल स्पष्टता का अभाव है और संभवतया आगामी बजट में सेवाओं पर करारोपण को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कुछ राज्यों में लगाए जाने वाले अतिरिक्त करों को भी हटाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में लगने वाला मंडी कर। बजट 2020-21 में कंपनियों को आयकर में आठ प्रतिशत की छूट दी जाए। मुद्रास्फीति और बढ़ती खर्च सीमा को देखते हुए व्यक्तिगत आयकर सीमा को बढ़ाकर व्यक्ति विशेष के लिए पांच लाख रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए छह लाख रुपये किया जाना चाहिए। छोटे कारोबारियों के लिए टीडीएस व्यवस्था काफी बोझिल है। आगामी बजट में इस प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही यह व्यवस्था की जाए कि पैन संख्या के साथ होने वाले भुगतान के लिए छोटी कंपनियों को टीडीएस न देना पड़े। साथ ही, एमएसएमई कंपनियों को साल में चार बार टीडीएस भरने के बजाय इसे सालाना एक बार किया जाना चाहिए। वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए बजट 2020-21 में आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की राहत देनी होंगी।

बातचीत: वीरेश्वर तोमर

पंकज कुमार
अध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

पुरस्कृत पत्र

सभी क्षेत्रों पर बराबर ध्यान देने की जरूरत

सरकार को 5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जिसमें बुनियादी ढांचा, एमएसएमई क्षेत्र व डिजिटल इंडिया पर जोर देने वाला बजट होना चाहिए। इसके लिए बजट में अधिक वित्त आवंटन पर ध्यान देना होगा, ताकि समावेशी विकास हो सके। निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था बनाने व आयात प्रतिस्थापन्न, नए उद्योग, ट्रेड पार्क आदि विकसित करने के लिए वित्त का अबाध प्रवाह जरूरी है। ताकि रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो सके। प्रदूषण संबंधी वैश्विक मानकों की प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा विकास पर बल देना होगा। इनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रावधान करने होंगे। भौतिक व सामाजिक अवसंरचना के लिए वित्त पोषण के लिए बॉन्ड बाजार बेहतर बनाने होंगे।

1

गिरधारी लाल टाक
जोधपुर, राजस्थान

पुरस्कार राशि
500 रुपये

श्रेष्ठ पत्र

मनोहरलाल उपाध्याय
इंदौर, मध्य प्रदेश

सर्वजन हिताय हो बजट

वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण इस बार का आम बजट कई तरह से महत्त्वपूर्ण रहेगा। बजट आर्थिक सुस्ती से निपटने और भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर सर्वजन हिताय वाला होना चाहिए। देश की लगभग 60 फीसदी से अधिक आबादी कृषि और संलग्न गतिविधियों पर निर्भर है। इसलिए आम बजट में कृषि उत्पादन बढ़ाने और उसके लिए उन्नत तकनीक व आधुनिक उपकरण और कृषि आय बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। आम नागरिक का पूंजीगत व्यय या लाभ, राजकोषीय फिसलन अथवा जीडीपी में घट बढ़ से सीधा वास्ता नहीं है, उसे तो महंगाई पर नियंत्रण चाहिए। बजट वाहन उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण, आईटी क्षेत्र को बढ़ावा, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के साथ ही रोजगारन्मुखी हो। बजट में आंतरिक व वाह्य सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए।

दीप कुमार
महराजगंज,उत्तर प्रदेश

रोजगार सृजन वाला हो

बजट में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की समस्याओं को तत्काल दूर करने तथा कृषि क्षेत्र में सहकारी खेती शुरू करने के प्रावधान होने चाहिए। इससे आर्थिक सुस्ती दूर होगी तथा रोजगार सृजन होगा। भारत में विनिर्माण के लिए नए निवेश को आकर्षित करने वाले आयातित उत्पादों को मुक्त व्यापार समझौते के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रत्येक एक करोड़ रुपये के निवेश में 50 लोगों और उससे अधिक लोगों को रोजगार देने वाले उद्योग को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में माना जाना चाहिए। 20 फीसदी से अधिक महिलाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों को 1 फीसदी की समग्र कर छूट देने की जरूरत है। निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए कम से कम 3 से 5 वर्ष के लिए नीति में स्थायित्व की आवश्यकता है। निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के लिए सरकार के हस्तक्षेप की भी जरूरत है।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

आर्थिक स्थिति हो मजबूत

महंगाई को देखते हुए बजट में रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजों के दाम को नियंत्रित रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। शिक्षा, रोजगार और कृषि जैसे मुद्दों पर सरकार को मात्र बजट में ही नहीं बल्कि विकास के लिए बनाए जाने वाली नीतियों में भी गंभीरता दिखानी चाहिए। हालांकि सरकार की नीतियों या कार्यप्रणाली में कमियों या दोष के कारण आज भी देश में शिक्षा, रोजगार और कृषि क्षेत्र में अनेक समस्याएं नजर आती हैं। इसके लिए आर्थिक फायदा देने वाली नीतियां बनें। लोग सरकार से मुफ्त बिजली, पानी या अन्य सुविधाओं तथा आयकर में काफी छूट की उम्मीद रखते हैं। लेकिन यह शायद ही कोई सोचता होगा कि अगर सरकार हर सुविधा मुफ्त में देने लगे और करों में भी भारी छूट दे तो उसकी कमाई कहां से होगी।

दिव्या प्रीत सेठी
नोएडा, उत्तर प्रदेश

हर वर्ग के लोगों का हो

रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ आज देश को बेहतर शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की भी जरूरत है। ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर वाहनों की बिक्री पर असर पड़ता है। ऐसे में कृत्रिम ईंधन का विकल्प तैयार किया जाना चाहिए। प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहन देना भी अच्छा विकल्प है। आशा है कि आम बजट के बेहतर परिणाम सामने आएंगे, जब मोदी सरकार बजट के घिसे पिटे फॉर्मूले की जगह व्यावहारिक और जमीनी स्तर पर समाज के हर तबके को तरजीह देगी, जिसमें महिलाओं, वरिष्ठ नागरिक, गरीब, मध्य आय वर्ग, हर वर्ग के व्यवसायी, छात्र, मजदूर, नियोक्ता और अंत्योदय की भावना से नीति बने और उसका उचित क्रियान्वयन हो।

... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है -
कोरोना वायरस जैसी महामारी से कैसे बचें?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें:
बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in

नेपाल से सटे क्षेत्रों पर बढ़ी नजर

पड़ोसी देश में कोरोना वायरस के एक मामले की पुष्टि के बाद सतर्क सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बीमारी की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की

नेपाल में कोरोनावायरस के एक मामले की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार ने उससे सटे क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि नेपाल की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के पानीटंकी और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के झूलाघाट तथा जौलजीबी में स्वास्थ्यकर्मियों की टीम तैनात की गई हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने नेपाल की सीमा से सटे पांच राज्यों- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखो के साथ एक वीडियो-कॉन्फ्रेंस बैठक की अध्यक्षता की। इसका मकसद कोरोनावायरस की रोकथाम और नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा करना था। प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की।

रविवार तक 137 उड़ानों के जरिये भारत आने वाले 29,707 यात्रियों की कोरोनावायरस के संक्रमण के लक्षणों की जांच की गई और अभी तक भारत में कोई मामला सामने नहीं आया है। केरल और महाराष्ट्र में 100 से अधिक लोगों को निगरानी में रखा गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, 'नेपाल में कोरोनावायरस के मामले की पुष्टि के बाद नेपाल से प्रवेश के रास्ते पानीटंकी (पश्चिम बंगाल) में निगरानी बढ़ा दी गई है।'

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा सूदन ने सीमावर्ती राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की। राज्यों को बताया गया है कि उन्होंने सीमा पार से आने वाले लोगों की जांच के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। मंत्रालय ने सलाह दी है कि इस सप्ताह पंचायती राज विभाग के समन्वय में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाए ताकि सीमावर्ती गांवों में कोरोनावायरस बीमारी, इसके लक्षणों, रोकथाम के उपायों और जानकारी देने आदि के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

सूदन ने उन्हें सलाह दी कि होटल एसोसिएशनों के साथ समन्वय किया जाए ताकि इन राज्यों के धार्मिक और अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले नेपाल के पर्यटक खुद ही जानकारी देने के लिए आगे आएं।

उन्होंने राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि हवाई अड्डा अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए चिकित्सा अधिकारी तैनात किए जाएं। इसके अलावा इन हवाई अड्डों के लिए अस्पताल चिह्नित किए जाएं।

सूदन ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि संदिग्ध मामलों की पहचान, समय पर नमूनों के संग्रह से लेकर एनआईवी पुणे पहुंचाने में नियमों का पालन किया जाए। राज्यों को सलाह दी गई है कि राज्यों में विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों के बीच समन्वय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को अद्यतन जानकारी देने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।

हॉन्ग कॉन्ग में मास्क खरीदने के लिए लगी कतार *फोटो : पीटीआई*

सतर्क सरकार

- नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में स्वास्थ्यकर्मियों की टीम तैनात
- सीमावर्ती गांवों में ग्राम सभाओं के जरिये बीमारी को लेकर चलेगा जागरूकता अभियान
- गृह सचिव ने राज्यों के डीजीपी को दिए निर्देश

गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी के साथ बातचीत की और उन्हें सीमावर्ती इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में निर्देश दिए।

जहाजरानी मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय बंदरगाह प्राधिकरणों को आवश्यक सूचना भेज दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी चीन में कोरोनावायरस के प्रसार को मद्देनजर रखते हुए शनिवार को भारत की तैयारियों की समीक्षा की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा था कि सात यात्रियों के नमूने आईसीएमआर-एनआईवी पुणे लैब में भेजे गए हैं। चौबीस घंटे चालू रहने वाला एक एनसीडीसी कॉल सेंटर (+91-11-23978046) चालू कर दिया गया है। सात हवाई अड्डों- नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलूरु, हैदराबाद और कोच्चि में थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक जनवरी 2020 के बाद चीन की यात्रा करने वाले यात्रियों से आग्रह किया है कि अगर उनके बुखार, खांसी, स्वांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण हैं तो वे खुद ही नजदीकी अस्पताल आकर जानकारी दें। यह वायरस चीन के वुहान के सीफूड और पशुओं के बाजार से पैदा हुआ है और यह अमेरिका तक पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोनावायरस के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, स्वांस लेने में दिक्कत आदि शामिल हैं।

कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल टीम भेज दी है जो खासतौर पर चीन और नेपाल से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करेगी। प्रदेश की महानिदेशक (स्वास्थ्य) अमिता उप्रेती ने कहा, 'केंद्र से लोगों को स्क्रीन करने का परामर्श जारी होने के बाद हमने अपनी टीमें सभी जिलों में भेज दी हैं। चीन और नेपाल की सीमा से सटे जिलों चंपावत, चमोली और पिथौरागढ़ में स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस के लक्षणों की पहचान के लिए सीमा के दूसरी तरफ से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है।'

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन में कोरोनावायरस के मुख्य केंद्र वुहान प्रांत में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए उड़ानों का इंतजाम कराने की अपील की तथा कहा कि वहां जमीनी स्थिति और बिगड़ गई है। बिहार के सारण जिला निवासी कोरोनावायरस की एक संदिग्ध रोगी को सोमवार को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में भर्ती कराया गया।

वुहान में चीनी प्रधानमंत्री

चीन के प्रधानमंत्री ली कछयांग सोमवार को कोरोनावायरस प्रभावित वुहान शहर पहुंचे। कोई शीर्ष नेता पहली बार कोरोनावायरस का केंद्र बताए जा रहे इस शहर में पहुंचा है। चीन में अब तक कोरोनावायरस से 80 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके संक्रमण के 2,744 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को कहा कि देश में कोरोनावायरस के पांच मामलों की पुष्टि हो चुकी है तथा यहां इस विषाणु से संक्रमण के कुछ और मामले सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोनावायरस के संक्रमण की जांच के लिए चार चीनी नागरिकों समेत कम से कम पांच लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है। *एजेंसियां*

पश्चिम बंगाल में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ सोमवार को राज्य सरकार द्वारा पेश प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें इस कानून को तत्काल निरस्त करने और एनपीआर तथा प्रस्तावित एनआरसी को वापस लेने की मांग की गई।

प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून संविधान और मानवता के खिलाफ है। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि इस कानून को तत्काल निरस्त किया जाए। हम एनपीआर को भी निरस्त कराना चाहते हैं। प्रस्ताव का विपक्षी दलों कांग्रेस और माकपा नीत वाम मोर्चा दोनों ने समर्थन किया।' भाजपा विधायक दल ने प्रस्ताव का विरोध किया और सीएए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।

केरल, राजस्थान और पंजाब- नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पहले ही पारित कर चुके हैं। यह कानून राज्य में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच तकरार का नया मुद्दा बन कर उभरा है। एक ओर तृणमूल कांग्रेस इस विवादित कानून का पूरी ताकत के साथ विरोध कर रही है, दूसरी ओर भाजपा इसे लागू करने पर जोर दे रही है। इससे पहले राज्य विधानसभा ने सितंबर 2019 में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, जिसका भाजपा ने विरोध किया था।

एनएचआरसी पहुंची कांग्रेस

कांग्रेस सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) पहुंची और उत्तर प्रदेश में सीएए के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने वाले लोगों पर पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पार्टी ने दावा किया कि पीड़ितों को मामले से संबंधित एफआईआर में आरोपी बनाया गया है और इसमें किसी भी पुलिस अधिकारी का नाम शामिल नहीं है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल एनएचआरसी के शीर्ष अधिकारियों से मिला और 31 पृष्ठ की व्यापक प्रस्तुति सौंपी, जिसमें राज्य में कथित अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघनों के सबूत के रूप में वीडियो और तस्वीर शामिल हैं।

बातचीत कर रास्ता खुलवाएं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भाजपा के हमले पलटवार करते हुए सोमवार को केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह एवं दूसरे मंत्रियों को शाहीन बाग जाना चाहिए और लोगों से बातचीत कर रास्ता खुलवाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने यह दावा भी किया कि भाजपा शाहीन बाग में रास्ता खुलवाना ही नहीं चाहती और यह सड़क आठ फरवरी (मतदान के दिन) के बाद खुल जाएगी।

ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

भारत का आंतरिक मामला

यूरोपीय संघ (ईयू) के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल फ्रांस का मानना है कि नया नागरिकता कानून (सीएए) भारत का एक आतंरिक राजनीतिक विषय है। फ्रांसीसी राजनयिक सूत्रों ने सोमवार को यह कहा। यूरोपीय संघ की 751 सदस्यीय संसद में तकरीबन 600 सांसदों द्वारा संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ छह प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद यह कहा गया है। दरअसल, इन प्रस्तावों में कहा गया है कि इस कानून का लागू होना भारत की नागरिकता व्यवस्था में एक खतरनाक बदलाव को प्रदर्शित करता है।

भारत के नए नागरिकता कानून के खिलाफ यूरोपीय संसद में प्रस्तावित चर्चा और मतदान की पृष्ठभूमि में उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

सीएए पर यूरोपीय संघ (ईयू) के चर्चा करने की तैयारी के बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा, 'सच्चाई यह है कि यूरोपीय संघ सीएए पर चर्चा कर रहा है। इस सरकार ने नागरिकता कानून का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया है।' *बीएस/एजेंसी*

केंद्रीय बजट : शब्द जाल और आंकड़ों से परे की कहानी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस शनिवार को ऐसे समय में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी, जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। पेश हैं केंद्रीय बजट से जुड़े कुछ ऐतिहासिक एवं रोचक तथ्यः

स्वतंत्र भारत का पहला बजट

आर.के. षण्मुखम चेट्टी

26 नवंबर 1947 को देश का पहला बजट पेश किया। उन्होंने 1947-1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के तौर पर कार्य किया।

भारत गणराज्य का पहला बजट

जॉन मथाई, स्वतंत्र भारत के तीसरे वित्त मंत्री, वर्ष 1950 में भारत गणराज्य का पहला बजट पेश किया, हालांकि योजना आयोग के बढ़ते हस्तक्षेप को देखते हुए कुछ समय बाद ही इस्तीफा दे दिया।

सर्वाधिक बजट

इसके कई दावेदार हैं लेकिन वित्त मंत्री **मोरारजी देसाई** इनमें सबसे आगे हैं। वह 1959-64 और 1967-69 तक वित्त मंत्री रहे। उन्होंने 8 सालाना बजट और दो अंतरिम बजट प्रस्तुत किए, जिससे यह आंकड़ा 10 पर पहुंच गया। इसके बाद, पी चिदंबरम (नौ), प्रणव मुखर्जी (आठ), यशवंत सिन्हा (सात), यशवंतराव चव्हाण (सात), सीडी देशमुख (सात), मनमोहन सिंह (छह) और टीटी कृष्णमाचारी (छह) ने बजट प्रस्तुत किए।

सबसे लंबा भाषण

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वित्त मंत्री **सीतारमण** का भाषण और साल 2003-04 का जसवंत सिंह का बजट भाषण सबसे लंबे भाषणों में शामिल हैं। सिंह ने 2:12 घंटे का भाषण दिया तो वहीं विपक्षी दलों द्वारा बार-बार बाधा पहुंचाने के बाद सीतारमण ने 2:15 घंटे का बजट भाषण दिया।

सबसे छोटा भाषण

यह एक अंतरित बजट और आपातकाल के बाद पहला बजट था। 1977 के चुनाव नजदीक आने के साथ **हीरुभाई पटेल** ने स्वतंत्र भारत का सबसे छोटा बजट भाषण दिया।

बजट प्रस्तुत करने वाले प्रधानमंत्री

देश के तीन प्रधानमंत्रियों ने अपने पद पर रहते हुए बजट प्रस्तुत किया। **जवाहर लाल नेहरू** ने कृष्णामचारी के त्यागपत्र देने के बाद 1958-59 का बजट पेश किया। इंदिरा गांधी ने वर्, 1970-71 में बजट पेश किया और वीपी सिंह को वित्त मंत्री से हटाकर रक्षा मंत्री बनाने के बाद तत्कालीन प्रभानमंत्री राजीव गांधी ने 1987-88 का बजट पेश किया।

समय में बदलाव

वर्ष 2000-01 के बजट से पहले तक बजट शाम पांच बजे सदन पटल पर रखा जाता था। यह औपनिवेशिक काल की प्रथा थी जिसे **यशवंत सिन्हा** ने बदला और इस बार से दिन में 11 बजे बजट पेश किया जाने लगा।

तारीखों में बदलाव और विलय वाला बजट

तत्कालीन वित्त मंत्री **अरुण जेटली** द्वारा पेश वर्ष 2017-18 के बजट में पहली बार रेल बजट का विलय कर दिया गया। इस समय तक फरवरी की आखिरी तिथि को बजट पेश किया जाता था, जिसे बदलकर 1 फरवरी किया गया।

उदारीकरण वाला बजट

स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अहम बदलाव वाला बजट। इस समय भारत भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हाराव ने 1991-91 के बजट में वित्त मंत्री **मनमोहन सिंह** को देश की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था बनाने की सहमति दे दी।

ड्रीम बजट

तत्कालीन वित्त मंत्री **पी. चिदंबरम** द्वारा पेश किए गए वर्ष 1997-98 के बजट को ड्रीम बजट कहा गया। इसमें आयकर दरों को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया गया और कॉर्पोरेट कर की दरें घटाई गईं।

वैश्विक रैंकिंग में आईआईएम बेंगलूर भारत में शीर्ष पर

विनय उमरजी

फाइनैंशियल टाइम्स वैश्विक एमबीए रैंकिंग 2020 के अनुसार भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) बेंगलूरु भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर रहा है। प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल आईआईएम बेंगलूरु नई रैंकिंग में छह पायदान की छलांग लगाते हुए पिछले साल के 33वें स्थान से इस वर्ष 27वें स्थान पर आ गया है। इसके ठीक बाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) 28वें स्थान पर रहा। हालांकि आईएसबी की रैंकिंग में गिरावट आई है और पिछले वर्ष यह 24वें स्थान पर था।

एफटी वैश्विक एमबीए रैंकिंग सालाना आधार पर कार्य अनुभव रखने वाले छात्रों को एक वर्षीय तथा दो वर्षीय परास्नातक कार्यक्रम कराने वाले विश्व के शीर्ष 100 संस्थानों की सूची तैयार करती है। आईएसबी के अलावा आईआईएम संस्थान भी पहले से कार्य अनुभव रखने वाले छात्रों के लिए एक वर्षीय पाठ्यक्रम चलाते हैं।

आईआईएम कलकत्ता पिछले साल के 49वें स्थान में सुधार करते हुए इस बार 42वें स्थान पर आ गया। रैंकिंग के लिए जरूरी मानकों जैसे करियर संभावनाएं, महिला छात्रों का औसत, बोर्ड में अंतरराष्ट्रीय सदस्यों को शामिल करना और महिला अध्यापकों की संख्या आदि में आईआईएम कलकत्ता ने अपने करीबी भारतीय संस्थानों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

बिजनेस स्कूल में आने से पूर्व की नौकरी और पढ़ाई के बाद की नौकरी में करियर, वरिष्ठता तथा कंपनी के आकार के आधार पर तुलना करने के पैमाने पर वैश्विक स्तर पर आईआईएम कलकत्ता पांचवे और आईआईएम अहमदाबाद सातवें स्थान पर रहा। आईआईएम कलकत्ता की निदेशक अंजु सेठ के अनुसार यह रैंकिंग संस्थान के एमबीएएक्स प्रोग्राम को विश्व स्तर का बनाने हेतु अध्यापकों के परिश्रम तथा बेहतर परिणाम को दर्शाती है। वहीं, आईआईएम कलकत्ता में एमबीएएक्स प्रोग्राम के अध्यक्ष अमित धीमान का कहना है कि संस्थान ने एफटी वैश्विक एमबीए रैंकिंग में पिछले तीन वर्ष से लगातार सुधार किया है।

दूसरी ओर, आईआईएम अहमदाबाद अपने एक वर्षीय एमबीए कार्यक्रम के लिए एफटी वैश्विक एमबीए रैंकिंग में 14 स्थानों की गिरावट के साथ पिछले साल के 47वें स्थान से इस बार 61वें स्थान पर आ गया।

भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन

संस्थान	2020	2019
आईआईएम बेंगलूर	27	33
आईएसबी	28	24
आईआईएम कलकत्ता	42	49
आईआईएम अहमदाबाद	61	47

स्रोतः फाइनैंशियल टाइम्स वैश्विक एमबीए रैंकिंग

कर राजस्व लक्ष्य से 2.5 लाख करोड़ रुपये कम रहने के आसार

पृष्ठ 1 का शेष

अग्रिम अनुमानों के मुताबिक निवेश की थाह देने वाला सकल स्थायी पूंजी गठन (जीएफसीएफ) मौजूदा वित्त वर्ष में 15 साल के न्यूनतम स्तर 0.97 फीसदी रहने की आशंका है जो एक साल पहले करीब 10 फीसदी था। उद्योग जगत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की मांग की थी।

उद्योग संस्था सीआईआई ने कॉरपोरेट कर की 15 फीसदी की घटी दर को सभी विनिर्माण इकाइयों पर लागू करने की मांग की थी। सरकार ने इसे अक्टूबर, 2019 के बाद गठित होने वाली इकाइयों पर लागू करने की घोषणा की थी। मौजूदा वित्त वर्ष में राजस्व अनुमानों के पूरा होने की उम्मीद नहीं है। चालू वित्त वर्ष के बजट में 2018-19 के वास्तविक आंकड़े नहीं दिए गए थे, बल्कि अंतरिम बजट में संशोधित आंकड़े दिए गए थे। 2018-19 में वास्तविक आंकड़ों और संशोधित आंकड़ों में 1.68 लाख करोड़ रुपये का अंतर था। इस तरह 2018-19 के संशोधित आंकड़ों की तुलना में चालू वित्त वर्ष के लिए कर राजस्व संग्रह में मात्र 9.47 फीसदी की वृद्धि का अनुमान जताया गया था।

अलबत्ता, यह अनुमान वित्त वर्ष 2019 के वास्तविक आंकड़ों से 18.31 फीसदी अधिक है। अधिकारियों का कहना है कि कॉरपोरेट कर की दर में कटौती और गलत अनुमानों के कारण कर राजस्व लक्ष्य से 2.5 लाख करोड़ रुपये कम रह सकता है। अग्रिम अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिक विकास दर के 5 फीसदी रहने का अनुमान है जो एक दशक में सबसे कम है।

> वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिक विकास दर 5 फीसदी रहने का अनुमान है जो एक दशक में सबसे कम है

वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में इसके 12 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था। इस तरह उच्च नॉमिनल जीडीपी वृद्धि के आधार पर लगाया गया राजस्व अनुमान अब बहुत महत्त्वाकांक्षी साबित हो रहा है। यही वजह है कि मौजूदा कीमतों पर 2020-21 के लिए आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाना बेहद अहम होगा।